



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 12 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 21, 1947 शक संवत्) [संख्या 28

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	367—380	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	723—736	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1101-1144	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

**भाग 1**

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

**आबकारी विभाग**

अनुभाग-1

नियुक्ति

30 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 1323/ई-1/तेरह-2024-1571184—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ0प्र0 आबकारी विभाग के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से प्राविधिक अधिकारी (प्राविधिक सेवा) के पद पर संस्तुत/चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को निम्नवत शर्तों के अधीन आबकारी विभाग के प्राविधिक सेवा संवर्ग में प्राविधिक अधिकारी के साधारण वेतनमान (07 वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,57,700) में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रम सं0	मेरिट क्र0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का	जन्म तिथि	स्थायी पता
1	2	3	4	5
सर्वश्री—				
1	1	सागर धनराज पुत्र श्री देवी दीन गुप्ता	14.01.2000	246 2, हिन्द टायर गली नं0-1, गांधी नगर, महोबा, उ0प्र0 पिन-210427
2	2	भरत भारतीय पुत्र श्री बिरेन्द्र कुमार	20.10.1995	ग्राम-गोविन्दपुर, पोस्ट-बुनगपुर थाना-परवलपुर, जिला-नालंदा, बिहार पिन-803114

1— उक्त अभ्यर्थियों को आबकारी प्राविधिक अधिकारी सेवा नियमावली, 2021 के नियम-17(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। आबकारी प्राविधिक अधिकारी सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

2— उ0प्र0 आबकारी प्राविधिक अधिकारी सेवा संवर्ग में उक्त चयनित अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागसज द्वारा तैयार की गई ज्येष्ठता सूची के आधार पर यथासमय किया जायेगा।

3— नियुक्ति आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) करेंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

4— केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

5— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।

6— अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

7— एक से अधिक पत्नी न होने की घोषणा।

8— दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण पत्र।

9— समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा जिसकी वे स्थाई सदस्य हों। निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

10— राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

11— राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण पत्र।

12— इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

13— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता संबंधी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

14— कार्यालय, आबकारी आयुक्त उपरोक्त दोनों अभ्यर्थियों की औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं उक्त चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु प्राविधानानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

15— उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उम्मीदवार द्वारा अपने स्वः सत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

16— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

17— उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों व गेट प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर उनका चयन किया गया है, के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने अथवा उनके फर्जी पाये पर उनकी सेवा/अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त कर दिया जायेगा।

18— उक्त अभ्यर्थियों के संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा उनके समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों तथा डिग्रियों व अन्य समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन/आवश्यक जाँच कराकर ही पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ही उन्हें योगदान कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

19— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/उस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

20— सम्बन्धित प्राविधिक अधिकारियों पर उ0प्र0 आबकारी प्राविधिक सेवा नियमावली, 2021 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

21— उक्त अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार होंगे।

22— सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

वीना कुमारी,  
प्रमुख सचिव।

**आयुष विभाग**

अनुभाग-1

19 जुलाई, 2023 ई0

**औपबन्धिक नियुक्ति**

सं0 4127/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री स्वाती केसरवानी पुत्री अशोक केसरवानी का विवरण निम्नवत् है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री स्वाती केसरवानी	श्री अशोक केसरवानी	31	54100082783	प्रयागराज	निवासी-ग्राम व पोस्ट-सहसों, प्रयागराज-221507	जौनपुर

2— शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1)— अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)— अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी

जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)– उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(6)– अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

(i)– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii)– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii)– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4128/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्रीमती नम्रता मिश्रा पत्नी श्री अंकुर मणि त्रिपाठी का विवरण निम्नवत् है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती नम्रता मिश्रा	W/o श्री अंकुर मणि त्रिपाठी	87	54100101291	प्रयागराज	श्री राम चन्द्र मिश्रा, 274-जी-12, न्याय विहार कालोनी, शेरवानी नगर, सुलेमसराय, प्रयागराज-211001	कौशाम्बी

2— शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1)— अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)— अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)— उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)— नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(6)— अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

(i)— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii)— अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii)— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4129/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्रीमती रुचि यादव पत्नी श्री मनोज कुमार यादव का विवरण निम्नवत् है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती रुचि यादव	W/o श्री मनोज कुमार यादव	271	54100077435	प्रयागराज	निवासी-ग्राम-उत्तम गिरि की चकिया, पो0-फाफामऊ, बहमलपुर, प्रयागराज-211013	प्रतापगढ़

2— शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

(1)— अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)— अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)— उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)— नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(6)– अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

(i)– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii)– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii)– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

### नियुक्ती/तैनाती

सं0 4130/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री सना कौसर अंसारी	श्री अब्दुल हमीद अंसारी	121	54100096299	कानपुर देहात	64, फेथफुल गंज, कैण्ट, कानपुर-208004	कानपुर देहात

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।



(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4131/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री अमृत गोडबोले	श्री अरविन्द गोडबोले	35	54100081766	कानपुर	म0नं0-608, सत्यम विहार, आवास विकास स्कीम नं0-1, कल्याणपुर, कानपुर-208017	कन्नौज

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4132/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती आकांक्षा सचान	W/o श्री अमित सचान	367	54100101495	कानपुर देहात	निवासी-श्री प्रेम नारायण सचान, पंकज बुक डिपो, मेन रोड़, लक्ष्मीबाई नगर, पुखरायां, कानपुर देहात-209111	फतेहपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4133/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती उपासना सोनकर	W/o श्री रमाशंकर यादव	178	54100047531	कानपुर नगर	प्लॉट संख्या-368, रावतपुर, कानपुर नगर 208019	कानपुर देहात

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,  
लीना जौहरी,  
प्रमुख सचिव।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, १२ जुलाई, २०२५ ई० (आषाढ़ २१, १९४७ शक संवत्)

### भाग १-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

#### Administrative (E-I) Section

#### Notice

January 27, 2025

**No. 1474/XC-3/2025/Admin.(E-I)**—"January 28, 2025 and January 30, 2025 are declared as holidays in the High Court of Judicature at Allahabad (at Allahabad only) and in lieu thereof May 17, 2025 (Saturday) & August 23, 2025 (Saturday) are declared as Court working days."

By order of the Court,  
Rajeev Bharti,  
Registrar General.

### NOTIFICATION

August 30, 2024

**No. 1854/Admin. (Services)/2024**—Sushri Shweta Vishwakarma, Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Moradabad vice Smt. Srishti Pandey.

**No. 1855/Admin. (Services)/2024**—Smt. Srishti Pandey, Judicial Magistrate, First Class, Moradabad is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Bhadohi at Gyanpur vice Sushri Shinjini Yadav.

**No. 1856/Admin. (Services)/2024**—Sushri Shinjini Yadav, Judicial Magistrate, First Class, Bhadohi at

Gyanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bhadohi at Gyanpur.

**No. 1857/Admin. (Services)/2024**—Smt. Kamlesh Kumari, Additional Civil Judge (Junior Division), Bhadohi at Gyanpur is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Bhadohi at Gyanpur *vice* Sri Arijeet Singh.

**No. 1858/Admin. (Services)/2024**—Sri Arijeet Singh, Judicial Magistrate, First Class, Bhadohi at Gyanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bhadohi at Gyanpur.

**No. 1859/Admin. (Services)/2024**—Sri Deepankar, Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad to be Civil Judge (Junior Division), Thakurdwara (Moradabad) in the vacant court.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Thakurdwara (Moradabad).

**No. 1860/Admin. (Services)/2024**—Sri Yughul Shambhu, Additional Civil Judge (Senior Division), Varanasi to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Varanasi *vice* Sri Prashant Kumar Singh-II.

**No. 1861/Admin. (Services)/2024**—Sri Prashant Kumar Singh-II, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Varanasi to be Additional Chief Judicial Magistrate, Kairana (Shamli at Kairana) *vice* Sri Ashish Kamboj.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Kairana.

**No. 1862/Admin. (Services)/2024**—Sri Ashish Kamboj, Additional Chief Judicial Magistrate, Kairana (Shamli at Kairana) to be Civil Judge (Senior Division), Kairana (Shamli at Kairana) *vice* Smt. Shahnaz Ansari.

**No. 1863/Admin. (Services)/2024**—Smt. Shahnaz Ansari, Civil Judge (Senior Division), Kairana (Shamli at Kairana) to be Additional Chief Judicial Magistrate, Kasia (Kushi Nagar at Padrauna).

**No. 1864/Admin. (Services)/2024**—Sri Sachin Kumar Dixit, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Chitrakoot to be Civil Judge (Senior Division), Chitrakoot *vice* Sri Surya Kant Dhar Dubey.

**No. 1865/Admin. (Services)/2024**—Sri Surya Kant Dhar Dubey, Civil Judge (Senior Division), Chitrakoot to be Judge Small Causes Court, Bareilly *vice* Smt. Alka Pandey.

**No. 1866/Admin. (Services)/2024**—Smt. Alka Pandey, Judge Small Causes Court, Bareilly to be Chief Judicial Magistrate, Bareilly *vice* Sri Saurabh Kumar Verma.

**No. 1867/Admin. (Services)/2024**—Sri Saurabh Kumar Verma, Chief Judicial Magistrate, Bareilly to be Civil Judge (Senior Division), Bareilly *vice* Smt. Shweta Yadav-I.

**No. 1868/Admin. (Services)/2024**—Smt. Shweta Yadav-I, Civil Judge (Senior Division), Bareilly to be Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly *vice* Sri Suresh Kumar Dubey.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bareilly.

**No. 1869/Admin. (Services)/2024**—Sri Suresh Kumar Dubey, Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly.

**No. 1870/Admin. (Services)/2024**—Sushri Smriti Chaurasia, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bahraich to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur.



**No. 1871/Admin. (Services)/2024**—Smt. Kavita Kumari, Additional Chief Judicial Magistrate, Ballia to be Additional Chief Judicial Magistrate, Ballia *vice* Sushri Gargi Sharma.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Ballia.

**No. 1872/Admin. (Services)/2024**—Sushri Gargi Sharma, Additional Chief Judicial Magistrate, Ballia to be Civil Judge (Senior Division), Ballia *vice* Sri Parag Yadav.

**No. 1873/Admin. (Services)/2024**—Sri Parag Yadav, Civil Judge (Senior Division), Ballia to be Chief Judicial Magistrate, Ballia *vice* Sushri Shambhavi Yadav.

**No. 1874/Admin. (Services)/2024**—Sushri Shambhavi Yadav, Chief Judicial Magistrate, Ballia to be Civil Judge (Senior Division), Barabanki *vice* Sushri Ruchi Tiwari.

**No. 1875/Admin. (Services)/2024**—Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (Senior Division), Barabanki to be Additional Chief Judicial Magistrate, Barabanki *vice* Smt. Shivani Rawat.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Barabanki.

**No. 1876/Admin. (Services)/2024**—Smt. Shivani Rawat, Additional Chief Judicial Magistrate, Barabanki to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Barabanki.

**No. 1877/Admin. (Services)/2024**—Sri Sandeep Kumar, Additional Civil Judge (Senior Division), Chandauli to be Civil Judge (Senior Division), Chandauli *vice* Smt. Suman Tiwari.

**No. 1878/Admin. (Services)/2024**—Smt. Suman Tiwari, Civil Judge (Senior Division), Chandauli to be Civil Judge (Senior Division), Budaun *vice* Sri Leelu.

**No. 1879/Admin. (Services)/2024**—Sri Leelu, Civil Judge (Senior Division), Budaun to be Additional Chief Judicial Magistrate, Budaun *vice* Sushri Richa Sharma.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Budaun.

**No. 1880/Admin. (Services)/2024**—Sushri Richa Sharma, Additional Chief Judicial Magistrate, Budaun to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Budaun.

**No. 1881/Admin. (Services)/2024**—Sri Amit Kumar Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Budaun to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Budaun *vice* Sri Manish Kumar-III.

**No. 1882/Admin. (Services)/2024**—Sri Manish Kumar-III, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Budaun to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Gorakhpur *vice* Sri Arpit Panwar.

**No. 1883/Admin. (Services)/2024**—Sri Arpit Panwar, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Gorakhpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur.

**No. 1884/Admin. (Services)/2024**—Smt. Vandana Agarwal, Additional Civil Judge (Senior Division), Hamirpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Hamirpur *vice* Smt. Nitisha Singh.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Hamirpur.

**No. 1885/Admin. (Services)/2024**—Smt. Nitisha Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Hamirpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

**No. 1886/Admin. (Services)/2024**—Sri Prashant Mishra-II, - Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Amroha to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi.

**No. 1887/Admin. (Services)/2024**—Sri Sanjay Raj Pande, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Sant Kabir Nagar to be Civil Judge (Senior Division), Sant Kabir Nagar *vice* Smt. Chetna Tyagi.

**No. 1888/Admin. (Services)/2024**—Smt. Chetna Tyagi, Civil Judge (Senior Division), Sant Kabir Nagar to be Chief Judicial Magistrate, Sant Kabir Nagar *vice* Sri Anil Kumar-XI.

**No. 1889/Admin. (Services)/2024**—Sri Anil Kumar-XI, Chief Judicial Magistrate, Sant Kabir Nagar to be Chief Judicial Magistrate, Etah *vice* Smt. Kamayani Dubey.

**No. 1890/Admin. (Services)/2024**—Smt. Kamayani Dubey, Chief Judicial Magistrate, Etah to be Civil Judge (Senior Division), Etah *vice* Smt. Surekha.

**No. 1891/Admin. (Services)/2024**—Smt. Surekha, Civil Judge (Senior Division), Etah to be Additional Chief Judicial Magistrate, Etah *vice* Smt. Charu Singh-I.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Etah.

**No. 1892/Admin. (Services)/2024**—Smt. Charu Singh-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Etah to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Etah.

**No. 1893/Admin. (Services)/2024**—Sri Mritunjay Kumar, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Hardoi to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

**No. 1894/Admin. (Services)/2024**—Smt. Pallavi Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Mirzapur *vice* Sri Vikash Kumar Singh.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mirzapur.

**No. 1895/Admin. (Services)/2024**—Sri Vikash Kumar Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Civil Judge (Senior Division), Mirzapur *vice* Sushri Pragya Singh-III.

**No. 1896/Admin. (Services)/2024**—Sushri Pragya Singh-II, Civil Judge (Senior Division), Mirzapur to be Chief Judicial Magistrate, Mirzapur *vice* Sri Sanjiv Kumar Tripathi.

**No. 1897/Admin. (Services)/2024**—Sri Sanjiv Kumar Tripathi, Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Chief Judicial Magistrate, Hathras *vice* Sri Jaihind Kumar Singh.

**No. 1898/Admin. (Services)/2024**—Sri Jaihind Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Hathras to be Civil Judge (Senior Division), Hathras *vice* Sri Munna Lal.

**No. 1899/Admin. (Services)/2024**—Sri Munna Lal, Civil Judge (Senior Division), Hathras to be Additional Chief Judicial Magistrate, Hathras *vice* Sri Deepak Nath Saraswati.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Hathras.

**No. 1900/Admin. (Services)/2024**—Sri Deepak Nath Saraswati, Additional Chief Judicial Magistrate, Hathras to be Additional Civil Judge (Senior Division), Hathras.

**No. 1901/Admin. (Services)/2024**—Sri Virendra Kumar-IV, Additional Civil Judge (Senior Division), Bahraich to be Additional Chief Judicial Magistrate, Bahraich *vice* Sri Krishna Kumar-VII.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bahraich.

**No. 1902/Admin. (Services)/2024**—Sri Krishna Kumar-VII, Additional Chief Judicial Magistrate, Bahraich to be Civil Judge (Senior Division), Bahraich *vice* Smt. Pratibha Chaudhary.

**No. 1903/Admin. (Services)/2024**—Smt. Pratibha Chaudhary, Civil Judge (Senior Division), Bahraich to be Chief Judicial Magistrate, Bahraich *vice* Sri Shivendra Kumar Mishra.

**No. 1904/Admin. (Services)/2024**—Sri Shivendra Kumar Mishra, Chief Judicial Magistrate, Bahraich to be Civil Judge (Senior Division), Malihabad at Lucknow *vice* Sri Kuwar Mitresh Singh Kushwaha.

**No. 1905/Admin. (Services)/2024**—Sri Kuwar Mitresh Singh Kushwaha, Civil Judge (Senior Division), Malihabad at Lucknow to be Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Sri Anand Mishra.

**No. 1906/Admin. (Services)/2024**—Sri Anand Mishra, Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Sri Peeyush Tripathi.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Lucknow.

**No. 1907/Admin. (Services)/2024**—Sri Peeyush Tripathi, Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

September 04, 2024

**No. 1908/Admin. (Services)/2024**—Sri Surender Kumar, Registrar (Judicial) (Enquiry), High Court of Judicature at Allahabad to be Registrar (Judicial) (Services), High Court of Judicature at Allahabad.

September 10, 2024

**No. 1909/Admin. (Services)/2024**—Pursuant to the letter no. FNo. 2/3/2024-Estt./NCLAT, dated 30.08.2024, issued by the National Company Law Appellate Tribunal, New Delhi, Sri Sunit Chandra (Sonu), Presiding Officer, Commercial Court, Gautambuddha Nagar is appointed/posted as Registrar, National Company Law Appellate Tribunal, New Delhi on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the date of joining.

**No. 1910/Admin. (Services)/2024**—Sri Ramesh Chand-II, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Azamgarh for trying cases of crime against women *vice* Sri Jainuddin Ansari.

**No. 1911/Admin. (Services)/2024**—Sri Jainuddin Ansari, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Azamgarh in the court created under 14<sup>th</sup> Finance Commission *vice* Sri Arvind Verma.

**No. 1912/Admin. (Services)/2024**—Sri Arvind Verma, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Azamgarh to be Joint Registrar (Judicial) (Enquiry), High Court of Judicature at Allahabad.

By order of the Hon'ble Court,  
RAJEEV BHARTI,  
Registrar General.

# जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

## सिंचाई विभाग

### उत्तर प्रदेश सरकार

#### प्रारूप-18

#### नियम-20 का उपनियम (2)

#### (अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

#### अधिसूचना

दिनांक 03 जून, 2025 ई०

सं० 180—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-15, मुरादाबाद के माध्यम से सार्वजनिकप्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सय्यैद महमूदपुर माइनर के निर्माण हेतु जनपद सम्भल तहसील चंदौसी परगना चंदौसी ग्राम मऊ अस्सु में कुल 0.1236 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2— राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा ..... दिनांक ..... को अनुमोदित किया गया है।

3— सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है— लागू नहीं है।

4— भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है—

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर सम्भल/चंदौसी को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5— अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
संभल	चंदौसी	चंदौसी	मऊ अस्सु	367	0.0480
“	“	“	“	373	0.0756
योग—					0.1236

6— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी—** उक्त भूमि का स्थल नक्शा सम्भल के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा सें,  
राज्य सरकार/कलेक्टर।

## IRRIGATION DEPARTMENT

### FORM-18

#### [Sub-rule (2) of rule 20]

#### PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-Section (1) of Section 11 of the Act]

#### NOTIFICATION

*June 03, 2025*

No. 180— Under Sub Section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act 2013, Whereas of Government of Uttar Pradesh/Collector (For the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.1236 Hectares of land is required in the village Mau Assu, Pergana- Chandausi, Tehsil- Chandausi, District Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal stage-II Sayad Mehmoodpur, Minor through Madhya Ganga Canal Construction Div-15, Moradabad (name of requiring body).

2- Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated .....

3- The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:-N.A.

4- A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under—

.....  
.....

Deputy Collector/Assistant Collector Chandausi/Sambhal is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5- Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

**SCHEDULE**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Sambhal	Chandausi	Chandausi	Mau Assu	367	0.0480
”	”	”	”	373	0.0756
<b>Total</b>					<b>0.1236</b>

6- The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon the survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7- Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8- Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

By Order,

*State Government/Collector.*

### कार्यालय, पुलिस उपायुक्त, यातायात, लखनऊ

30 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 वाचक/डीसीपीटी/ई-रिक्शा(दिशा-निर्देश)/2023/34—राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सुगम बनाने के लिए ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में ई-रिक्शा परमिट व्यवस्था से मुक्त है जिस कारण इनका रूट निर्धारण संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। परन्तु धारा-31 पुलिस एक्ट के अनुसार सड़कों पर व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। इसी प्रकार मोटर वाहन अधिनियम की 1988 की धारा-115 एवं उ0प्र0 मोटर वाहन नियमावली 1998 के अधिनियम 178 में भी मोटर वाहनों के संचालन को नियंत्रित किये जाने हेतु पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। अतः मैं हृदेश कुमार, पुलिस उपायुक्त, यातायात इन अधिनियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई-रिक्शा के रूट निर्धारण हेतु निम्नांकित व्यवस्थायें 01 जनवरी, 2024 से लागू करता हूँ—

1— समस्त जनपद को एसीपी के क्षेत्र के अनुसार 16 जोन में बांटा गया है जिसमें लगभग तीन थाने होते हैं। किसी भी ई-रिक्शा को एक जोन में ही चलना अनुमत्य होगा। जिसके लिए उन्हें एक फॉर्म निर्गत किया जा रहा है जिसमें वो 3 जोन का विकल्प भरकर बतायेंगे। यह फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध होगा एवं किसी भी थाने पर जमा किया जा सकेगा। थानो द्वारा फॉर्म की ऑनलाइन एन्ट्री की जायेगी। फॉर्म की प्राप्ति रसीद को ई-रिक्शा पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

2— विकल्प के आधार पर यथासंभव ई-रिक्शा को जोन आवंटित किये जायेंगे। परन्तु यदि किसी जोन में ज्यादा संख्या में आवेदक है तो वहां लॉटरी व्यवस्था अथवा अन्य कोई निर्विवादित तरीके से जोन आवंटित किया

जायेगा। 16 जोन में देहात जोन में मांग कम होगी एवं शहरी जोन में मांग अधिक होगी जिसे विचार-विमर्श के अनुसार वितरण किया जायेगा। ताकि किसी भी जोन में अधिक ई-रिक्शा न चलें।

3— जोन आबंटन के पश्चात समस्त ई-रिक्शा को कलर कोडेड स्टिकर्स निर्गत किये जायेंगे। जिसके आधार पर पहचान होगी कि वे अपने जोन में चल रहे हैं या किसी अन्य जोन में चल रहे हैं। यह स्टिकर्स यातायात पुलिस द्वारा तैयार कराकर अपने कार्यालय या थानों के माध्यम से वितरित कराये जायेंगे। इसे ई-रिक्शा के स्क्रीन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

4— संभागीय परिवहन अधिकारी को भी इस फॉर्म को उपलब्ध कराया जा रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आर0सी0 निर्गत करने के पूर्व यह फॉर्म भरकर अवश्य जमा करा लिया गया हो। प्राप्ति रसीद पर संभागीय परिवहन अधिकारी की मुहर थाने के स्थान पर लगायी जा सकेगी। इस फॉर्म को भरवाकर इसकी कॉपी जमा होने पर ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्गत करेंगे। भविष्य में इसे ऑनलाइन लखनऊ पुलिस की साइट पर कर दिया जायेगा तो नये ई-रिक्शा आवेदक ये फॉर्म भर सकते हैं एवं इसका प्रिंट आउट संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में जमा करने पर आर0सी0 निर्गत किया जा सकेगा।

5— चालकों एवं मालिकों का मोबाइल नंबर, आपराधिक इतिहास, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की भी जानकारी का डाटाबेस तैयार किया जायेगा। जिसे भविष्य में ऑनलाइन किया जायेगा। फॉर्म में अंकित सूचना भरकर देना अनिवार्य होगा।

6— ई-रिक्शा का स्वामी या चालक बदलने पर उनके द्वारा इसकी सूचना नये स्वामी/चालक के पूर्ण विवरण के साथ यातायात कार्यालय को 03 दिवस में देना अनिवार्य होगा।

7— जोन आबंटन के पश्चात् सहायक पुलिस उपायुक्त की संस्तुति के आधार पर पुलिस उपायुक्त जोन द्वारा जोन के अंतर्गत पुनः अंतिम रूट निर्धारण किया जायेगा।

8— एक जोन से अधिक जोन में पड़ने वाले रूट का निर्धारण संयुक्त पुलिस आयुक्त, (कानून एवं व्यवस्था) द्वारा पुलिस उपायुक्त, यातायात की संस्तुति पर किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 15 जनवरी, 2024 तक लगभग साठ हजार फॉर्म छपवाकर निःशुल्क बँटवाये जायेंगे एवं 30 जनवरी, 2024 तक समस्त फॉर्म भरकर जमा करना होगा। फरवरी प्रथम सप्ताह में जोन का आबंटन सुनिश्चित किया जायेगा एवं फरवरी माह में ही कलर कोड स्टिकर्स आवंटित किये जायेंगे। स्टिकर्स पर क्यूआर कोड पड़ा होगा, जिसको स्कैन करने पर उसकी समस्त बेसिक डिटेल ज्ञात हो जायेगी। साथ ही लखनऊ वेबसाइट पर भी रिक्शा का नंबर भरकर विवरण रखा जा सकेगा। व्यवस्था को लागू करने हेतु अन्य आदेश अलग से आवश्यकतानुसार निर्गत किये जायेंगे।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम व पुलिस अधिनियम तथा अन्य सुसंगत दण्डिक प्राविधानों के तहत विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।

11 जून, 2024 ई0

सं0 वाचक/डीसीपीटी-(ई-रिक्शा आदेश)/2024/1620—राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सुगम बनाने के लिए ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। पुलिस एक्ट की धारा-31 के अनुसार सड़कों पर व्यवस्था बनाये रखने तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 एवं उ0प्र0 मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 178 में मोटर वाहनों के संचालन को नियंत्रित किये जाने का पर्याप्त अधिकार पुलिस अधीक्षक को प्रदान किया गया है। वर्तमान में जनपद-लखनऊ में लगभग 53,361 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं जो परमिट व्यवस्था से मुक्त हैं। ऐसे में यह पाया गया है कि सभी ई-रिक्शा कुछ ही क्षेत्र में ज्यादा संख्या में चल रहे हैं जैसे— चारबाग रेलवे स्टेशन, चरक चौराहा, अवध चौराहा, पॉलीटेक्निक चौराहा आदि-आदि। वर्तमान में इस पर किसी भी

तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है न ही इनके लिए किसी तरह का रूट निर्धारण किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो रहा है। कैसरबाग चौराहा, पॉलीटेक्निक चौराहा, कमता चौराहा पर अत्यधिक संख्या में ई-रिक्शा होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में आने जाने वाले न्यायमूर्तियों, अधिवक्ताओं, वादकारियों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों में आने जाने वाले अधिकारियों आदि को असुविधा उत्पन्न हो रही है, जिससे जनहित प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार चारबाग स्टेशन आदि पर अधिक संख्या में होने के कारण यात्रियों के रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने में भी असुविधा हो रही है। व्यापार मण्डल एवं मीडिया द्वारा भी बेलगाम ई-रिक्शा की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में समय समय पर दाखिल किये जाने वाली जनहित याचिकाओं में भी इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया था। इसलिए इसे विनियमित किये जाने की महती आवश्यकता है।

उपरोक्त विधिक प्राविधानों में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व में ई-रिक्शा के रूट/क्षेत्र निर्धारण हेतु कतिपय व्यवस्थाएँ इस कार्यालय के द्वारा लागू की गयी हैं। इन व्यवस्थाओं में सर्वप्रथम समस्त ई-रिक्शा चालकों को निःशुल्क फॉर्म वितरण कर इनसे इनके नाम, पता एवं तीन जोनों का विकल्प देते हुए विवरण आदि मांगा गया। यह आदेश दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 को निर्गत किया गया था (संलग्न-01)। जनपद लखनऊ में कुल 16 सर्किल हैं जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी नियुक्त हैं। इन 16 सर्किलों में प्रत्येक में लगभग तीन थाने हैं। इन 16 सर्किलों को 16 जोन के रूप में विभक्त किया गया, जिनके अंतर्गत ही ई-रिक्शा का संचालन करने के लिए व्यवस्था की जा रही है क्योंकि ई-रिक्शा “लास्ट माईल कनेक्टिविटी” अर्थात् मुख्य मार्गों से अपने घरों तक लोग आसानी से जा सके इस प्रयोजन के लिए ही लॉन्च किये गये थे। वर्तमान में इनसे फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया ऑफलाइन पूर्ण की जा चुकी है एवं अब ऑनलाइन विकल्प भी दे दिया गया है। जहां ये रूट/क्षेत्र हेतु अपना फॉर्म भर सकते हैं। रिक्ति के सापेक्ष कतिपय जोन में मांग अधिक होने के कारण निष्पक्षता के दृष्टिगत लॉटरी द्वारा आवंटित किया जा रहा है।

अब तक समस्त थानों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 26,890 फॉर्म ई-रिक्शा चालकों द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन भरे गये हैं, जिनमें उनके द्वारा तीन जोनों का विकल्प दिया गया है। इन 26,890 फॉर्म में से कतिपय फॉर्म गैर जनपदों से रजिस्टर्ड ई-रिक्शा मालिकों के द्वारा भरे गये हैं जिन्हें जनपद लखनऊ में चलने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः ऐसे 666 फॉर्म को निस्तारित किया जा रहा है। कतिपय फॉर्म दोबारा भरे गये हैं ऐसे 2369 फॉर्म भी निस्तारित किये जा रहे हैं। पुनः 94 फॉर्म ऐसे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्राप्त है अतः इन्हें अभी रूट/क्षेत्र देने का औचित्य नहीं है। इस प्रकार 26,890 फॉर्म भरे गये जिसमें (26890-666-2369-94) 23761 फॉर्म लॉटरी की तिथि 11 जून, 2024 तक सही एवं लॉटरी हेतु उपयुक्त पाये गये हैं। संपूर्ण फॉर्म का विवरण जिसमें उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं उस जोन में आवंटन हेतु ई-रिक्शा की रिक्ति आदि (संलग्नक-02) के रूप में इस आदेश के साथ संलग्न है। उल्लेखनीय है कि जोन में जो रिक्ति है उसे निर्धारण करने हेतु मुख्य रूप से समस्त यातायात क्षेत्रों के समस्त यातायात निरीक्षक एवं यातायात उपनिरीक्षक की बैठक कर उनसे वार्ता की गयी एवं उस क्षेत्र में एक सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जोन हेतु 500 का निर्धारण किया गया एवं इस बात पर जोर दिया गया कि शहर के जिस क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में ई-रिक्शा चल रहे हैं प्रारम्भ में 500 ई-रिक्शा की ही अनुमति दी जाये, क्योंकि उस क्षेत्र में ई-रिक्शा की कमी महसूस होने पर लॉटरी के माध्यम से पुनः अतिरिक्त आवंटन किया जा सकेगा, परन्तु यदि मांग की अपेक्षा ज्यादा ई-रिक्शा आवंटित कर दिये जाते हैं तो उन्हें वहां से हटाया जाना मुश्किल होगा एवं यह पूरी प्रक्रिया औचित्यहीन हो जायेगी। पुनः शहर में ई-ऑटो 5930 अन्य ऑटो रिक्शा 4343 विक्रम ऑटो -2523 चल रहे हैं। साथ ही सिटी बस एवं मेट्रो सेवा भी प्रचलित है। अतः ई-रिक्शा के अलावा भी अन्य साधन शहर में जन सामान्य के लिए पर्याप्त उपलब्ध हैं।

चार्ट से स्पष्ट है कि ज्यादातर ई-रिक्शा चालकों द्वारा प्रथम विकल्प शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र जहां अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि स्थित हैं में दिया गया है, जबकि वहां आवश्यकता उतनी ई-रिक्शा की नहीं है। ऐसे में जहां कहीं भी रिक्ति के सापेक्ष अधिक मांग है वहां कंप्यूटर से लॉटरी निकालकर उन्हें उनका क्षेत्र आवंटित किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप चौक क्षेत्र में लगभग 6056 ई-रिक्शा चालकों ने विकल्प भरा है जबकि वहां आवश्यकता 500 ई-रिक्शा की ही है। ऐसे में उन 6056 लोगों को उस लॉटरी में सम्मिलित करते हुए जोन संख्या-IV के लिए लॉटरी कम्प्यूटर



द्वारा निकालकर 500 लोगों को यह जोन आवंटित किया जायेगा। शेष 5556 लोगों को द्वितीय विकल्प के लिए विचार किया जायेगा और यदि इनके द्वितीय व अग्रेतर विकल्प उस क्षेत्र के ई-रिक्शा आवंटियों को प्रथम विकल्प के रूप में आवंटन से भरा जा चुका होगा तो इनके स्वतः वैसे जोन आवंटित होंगे जहाँ रिक्ति उपलब्ध होगी। यही प्रक्रिया सभी जोन के लिए अपनायी जायेगी। इस प्रकार यह लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए समस्त ई-रिक्शा चालकों जिसकी संख्या लगभग 23761 है को उनका क्षेत्र आवंटन कर दिया जायेगा। लॉटरी की तिथि के बाद ऑनलाइन रूट के लिए छूटे हुए आवेदन भरे जाने पर उन्हें भरे जाने से रिक्त-क्षेत्र या देहात क्षेत्र के जोन दिये जा सकेंगे।

पुनः लॉटरी से क्षेत्र/रूट आवंटन के पश्चात समस्त ई-रिक्शा चालकों के पास एक माह का समय होगा जिसमें वे लखनऊ पुलिस की बेबसाइट से अपना कलर कोड स्टीकर जिसमें क्षेत्र, जोन, थाना आदि की सूचना उपलब्ध होगी निकालकर सभी ई-रिक्शा चालक कलर कोडेड स्टीकर अपनी ई-रिक्शा पर चस्पा कर चलेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यातायात कार्यालय से भी यह स्टीकर्स प्राप्त कर सकेंगे। एक माह के पश्चात ऐसे समस्त ई-रिक्शा जिन्होंने किसी रूट के लिए आदेश नहीं दिया है एवं जिन्हें रूट का स्टीकर नहीं प्राप्त है, उन सभी को मार्गों से हटाने के लिए नियमानुसार चालान आदि की कार्यवाही की जायेगी। पुनः ऐसे ई-रिक्शा चालक जिन्होंने निर्धारित रूट प्राप्त कर लिया है उन्हें सुनिश्चित किया जायेगा कि वे अपने क्षेत्र में ही सवारी को लेकर चलेंगे व उस क्षेत्र के ही महत्वपूर्ण चौराहों पर 100 मीटर की दूरी पर निर्धारित स्थल पर खड़े होंगे, जिससे यातायात अनावश्यक रूप से बाधित न हो और आम जनमानस आदि को तथा सामान्य यातायात के संचालन में असुविधा न हो व यातायात को विनियमित किया जा सके। इसी एक माह में आपत्ति/सुझाव भी दे सकेंगे।

यहां यह संभव है कि ई-रिक्शा चालक शहर में निवास करते हों एवं देहात में उनको क्षेत्र आवंटित किया गया हो ऐसे में अपने क्षेत्र में खाली ई-रिक्शा ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे एवं पुलिस खाली ई-रिक्शा का चालान नहीं करेगी एवं यह माना जायेगा कि वो अपने क्षेत्र में जाने के लिए अन्य क्षेत्र से गुजर रहे हैं परन्तु जिस क्षेत्र में आवंटन है उस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में यदि सवारी को लेकर चलाते हुए पाये जायेंगे अथवा चौराहों पर सवारी भरने हेतु खड़े पाये जायेंगे तो इसे रूट उल्लंघन एवं उपरोक्त अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह रूट आवंटन एक वर्ष के लिए मान्य होगा एवं एक वर्ष के पश्चात पुनः लॉटरी आवंटन चेंज किया जायेगा ताकि समस्त ई-रिक्शा चालकों को समान रूप से शहर में चलने का समान अवसर प्राप्त हो।

पुनः समस्त जोन के कलर कोड निर्धारित किये गये हैं। पाँच पुलिस उपायुक्त के पाँच प्रमुख कलर (लाल, हरा, नीला, काला, पीला) स्टीकर के आधे ऊपरी भाग में होंगे। एवं पुलिस उपायुक्त के सहायक पुलिस आयुक्त का कलर उन पाँच कलर के साथ बचे आधे भाग पर होंगे। यह चार्ट (संलग्नक-03) के रूप में संलग्न है।

यदि कोई रिक्शा चालक फर्जी कूटरचित स्टीकर लगाकर ई-रिक्शा का चालन करें तो यह क्यूआर कोड स्कैनिंग में पकड़ा जा सकेगा। पकड़े जाने पर एमवीएक्ट व भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जायेगी।

कम्प्यूटर से लॉटरी दिनांक 11 जून, 2024 को रिक्शा चालकों के समक्ष निकाली जायेगी। जिसकी सूचना अखबारों में दी गयी है। समस्त अखबार कटिंग (संलग्नक-04) के रूप में लगे हैं। सॉफ्टवेयर की निष्पक्षता बनाये रखने के लिए कम्प्यूटर से आवंटन का ट्रायल चालकों द्वारा बतायी गयी संख्या (1 से अधिक) पर किया जायेगा। तत्पश्चात अंतिम बार सॉफ्टवेयर ट्रायल पूर्ण कराकर अंतिम लॉटरी निकाली जायेगी।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही निःशुल्क है एवं किसी भी कार्यालय में किसी भी तरह का कोई शुल्क देय नहीं है। यह आदेश पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

(ह0) आस्पष्ट

पुलिस उपायुक्त,

यातायात, लखनऊ।

## कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

01 जनवरी, 2025 ई0

सं0 01/जी-610/2016-17 निदेशालय के पत्र संख्या-2418/जी-610/2016-17 दिनांक 01 मई, 2018 द्वारा जनपद शाहजहाँपुर की तहसील सदर परगना कांट के ग्राम पलिहयूरा व हदीपुर कुरिया को जोत चकन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4क(2) के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की चकबन्दी क्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जिसमें ग्राम का त्रुटिपूर्ण नाम पलिहयूरा व हदीपुर कुरिया अंकित हो गया है। जबकि ग्राम का शुद्ध नाम पल्हौरा व हटीपुर कुरिया परगना कांट तहसील सदर जनपद शाहजहाँपुर होना चाहिए।

अतः निदेशालय के पत्र संख्या-2418/जी-610/2016-17 दिनांक 01 मई, 2018 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति त्रुटिपूर्ण अंकित जनपद शाहजहाँपुर की तहसील सदर परगना कांट के ग्राम पलिहयूरा व हदीपुर कुरिया जनपद शाहजहाँपुर के स्थान पर शुद्ध ग्राम का नाम पल्हौरा व हटीपुर कुरिया परगना कांट तहसील सदर जनपद शाहजहाँपुर पढ़ा जाय। शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

11 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 1789/जी0-237/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पीलीभीत परगना जहानाबाद जनपद पीलीभीत के ग्राम मीरापुर एहतमाली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1790/जी0-161/2023-24/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धनघटा परगना महुली पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम दौलतपुर, तप्पा-मुरादपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1791/जी0-7/2023-24/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मेहदावल परगना मगहर पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम ददरा, तप्पा-मेहदावल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1792/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित

होने के दिनांक से तहसील धनघटा परगना महुली पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम सियरखुर्द, तप्पा-सेमरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1793/जी0-154ए/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील करनैलगंज परगना ग्वारिच जनपद गोण्डा के ग्राम पूरे पाण्डेय में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1794/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना कर्वी जनपद चित्रकूट के ग्राम छेछरिया बुजुर्ग में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1795/जी0-15/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना परगना जगदीशपुर जनपद अमेठी के ग्राम गाईमऊ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1796/जी0-125/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अमेठी परगना आसल जनपद अमेठी के ग्राम मंगरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1797/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धनघटा परगना महुली पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम दुधरा तिवारी, तप्पा-सेमरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1798/जी0-15/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना परगना जगदीशपुर जनपद अमेठी के ग्राम काजीपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1799/जी0-167/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नर्वल जनपद कानपुर नगर के ग्राम टीकरभाऊ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1800/जी0-179/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील राबर्ट्सगंज परगना बड़हर जनपद सोनभद्र के ग्राम तुलसीपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1801/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरैया परगना अमोढ़ा जनपद बस्ती के ग्राम बंजरियासूबी, तप्पा-दुबौलिया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

भानु चन्द्र गोस्वामी,  
चकबन्दी संचालक,  
उत्तर प्रदेश।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, १२ जुलाई, २०२५ ई० (आषाढ़ २१, १९४७ शक संवत्)

### भाग ८

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

#### NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,  
Director.

### उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

#### भूमि अर्जन अनुभाग

(उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५)

(उ०प्र० अधिनियम संख्या-१, १९६६) की धारा-२८ के अधीन)

#### सूचना

१६ जून, २०२५ ई०

सं० ४४७/एल०ए०सी०/एच०क्यू०-उ०प्र० टाउनशिप नीति-२०२३ के अन्तर्गत निर्गत लाइसेन्स सं०-४०५०/सी०ए०पी०/२०२४ दिनांक १२ दिसम्बर, २०२४ के क्रम में विकासकर्ता मैसर्स शालीमार कॉर्प लि० द्वारा ग्राम-खजूरगाँव एवं तिन्दोला, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना सृजित की जा रही है, जिस हेतु उ०प्र० टाउनशिप नीति २०२३ के उपनियम के प्रस्तर ३.३(१०) के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश आवास एवं विकास

परिषद अधिनियम-1965 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार धारा-28 की अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है। उक्त इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं:-

**उत्तर:-** खसरा संख्या-306 (तिन्दोला मार्ग), ग्राम-तिन्दोला, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी, खसरा संख्या-21, 22, 23, 28भाग, 25भाग ग्राम-खजूरगांव, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी, खसरा संख्या-306 ग्राम तिन्दोला तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी, खसरा संख्या-26 ग्राम-खजूरगांव, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी, खसरा संख्या-306 (तिन्दोला मार्ग), ग्राम-तिन्दोला, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी, खसरा संख्या- 27भाग, 177, 178भाग ग्राम-खजूरगांव, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी, खसरा संख्या-398, 399 ग्राम-बरेठी, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी।

**पूर्व:-** खसरा संख्या-1, 2, 3, 4, 8 ग्राम-नगर, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी, खसरा संख्या-184/1578, 184 भाग, 188, 191 भाग, 190, 225, 228 भाग, 229 भाग, 230 भाग, 234, 232, 231, 240 भाग, 237, 236, 249, 250, 217, 216 भाग, 204 भाग, 251, 200 भाग, 199, 278, 146, 145 भाग, 148, 150 भाग, 148, 145, 339 भाग, 146, 278, 320 ग्राम-खजूरगांव, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी।

**दक्षिण:-**खसरा संख्या-331, 336, 341, 343, 345, 346, 134 भाग, 350, 132 भाग, 350 भाग, 349 भाग, 346, 347, 512, 357, 358, 359 भाग, 360, 457, 456, 415, 414, 383, 382 भाग, 384, 380 भाग, 384, 379, ग्राम-खजूरगांव, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी।

**पश्चिम:-**खसरा संख्या-322, 321, 318 ग्राम-तिन्दोला, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी, खसरा संख्या-376, 375 ग्राम-खजूरगांव, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी, खसरा संख्या-317, 316, 315, 326, 325 भाग, 340, 327 भाग, 312 ग्राम-तिन्दोला, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी, खसरा संख्या-02, 06, 11 भाग, 06, 07, 08 ग्राम-खजूरगांव, तहसील-नवाबगंज, परगना-देवा, जनपद-बाराबंकी।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र कार्यालय आवास आयुक्त,(भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-(226001) अथवा कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स अंगूरीबाग, अयोध्या-(224001) या कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, अंगूरीबाग, अयोध्या-(224001) में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित भूस्वामियों के निर्माणों पर उत्तर-प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम- 1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट/विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 के गजट प्रकाशन के तिथि से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, अंगूरीबाग, अयोध्या-(224001) में प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेंगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

**डा0 बलकार सिंह,**

आवास आयुक्त।

**UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD****[LAND ACQUISITION SECTION]**

[U. P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965]

(Notice under section-28 of U. P. Act No. 1, 1966)

**NOTICE***June 16, 2025*

**No. 447/L.A.C./H.Q.**--Under the U. P. Township Policy, in accordance with the License No. 4050/C.A.P./2024 dated 12.12.2024 issued for an Integrated Township Scheme is being created by the developer M/s. Shalimar Corp. Ltd. in Village-Khajoorgaon and Tindola, Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki, for which a notification of Section-28 is being published as per the provisions of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 as mentioned in clause 3.3 (10) of the by-law's of the U.P. Township Policy 2023. The boundaries of the area included in the said Integrated Township Scheme are as follows-

**North--**Khasra No. 306 (Tindola Road), Village-Tindola, Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki, Khasra No. 21, 22, 23, 28 Part, 25 Part Village-Khajoorgaon Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki, Khasra No. 306 (Tindola Road), Village-Tindola, Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki, Khasra No. 26 Village-Khajoorgaon, Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki, Khasra No. 306 (Tindola Road), Village-Tindola, Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki, Khasra No. 27 Part, 177, 178 Part Village-Khajoorgaon, Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki, Khasra No. 398, 399 Village-Barethi, Tehsil -Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki.

**East--**Khasra No. 1, 2, 3, 4, 8 Village-Nagar, Tehsil- Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki, Khasra No. 184/1578, 184 Part, 188, 191 Part, 190, 225, 228Part, 229Part, 230Part, 234, 232, 231, 240 Part, 237, 236, 249, 250, 217, 216 Part, 204 Part, 251, 200 Part, 199, 278, 146, 145 Part, 148, 150 Part, 148, 145, 339 Part, 146, 278, 320 Village- Khajoorgaon, Tehsil-Nawabganj, Pargana- Deva, District-Barabanki.

**South--**Khasra No. 331, 336, 341, 343, 345, 346, 134 Part, 350, 132 Part, 350 Part, 349 Part, 346, 347, 512, 357, 358, 359 Part, 360, 457, 456, 415, 414, 383, 382 Part, 384, 380, 384, 379 Village-Khajoorgaon, Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District- Barabanki.

**West--**Khasra No. 322, 321, 318 Village-Tindola, Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki, Khasra No. 376, 375 Village-Khajoorgaon, Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki, Khasra No. 317, 316, 315, 326, 325 Part, 340, 327 Part, 312 Village-Tindola, Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki, Khasra No. 02, 06, 11 Part, 06, 07, 08 Village-Khajoorgaon, Tehsil-Nawabganj, Pargana-Deva, District-Barabanki.

Details and map of the land included in the scheme can be seen in the Office of Housing Commissioner, (Land Acquisition Section) U.P. Housing and Development Board, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow (226001) or Office of Executive Engineer, Construction Division Ayodhya-01, U.P. Housing and Development Board, Office Complex Angooribagh, Ayodhya (224001) or Office of the Superintending Engineer, Ayodhya Circle, U.P. Housing and Development Board, Office Complex, Angooribagh, Ayodhya (224001) on any working day from 11:00 am. to 03:00 pm.

Betterment/Development fee will also be levied on the land owners of existing constructions situated in the scheme area as per the provisions of U.P. Awas EvamVikas Parishad Adhiniyam, 1965.

Objections against the scheme will be taken within 30 days from the date of First publication of this notice in the Gazette of U.P., at the Office of Housing Commissioner, Land Acquisition Section, U.P. Housing and Development Board, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or at the Office of Executive Engineer, Construction Division Ayodhya 01, U.P. Housing and Development Board, Office Complex, Angooribagh, Ayodhya (224001). No objections will be accepted after the given time. The objection should clearly mention the correct name of the Scheme and the name of the objector's land/building/village included in the Scheme/Khasra No./area of land and all other details.

Dr. Balkar Singh,  
Housing Commissioner.

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या-1, सन् 1966)

(उ०प्र० अधिनियम संख्या-7 सन् 2010 द्वारा संशोधित) की धारा-33 एवं

अनुसूची (धारा-55) की धारा-2 (3) सपठित धारा-32 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना

अधिसूचना

16 जून, 2025 ई०

सं० 443/एल०ए०सी०/एच०क्यू०-(पत्रावली-59)-परिषद के पत्र संख्या-1245/भू०अ०-दो दिनांक 17 जुलाई, 2004 द्वारा परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-बरौली खलीलाबाद, खसरा संख्या-1666 की अवशेष भूमि क्षेत्रफल 2.642 हेक्टेयर को सम्मिलित करते हुए उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-28 के अन्तर्गत योजना की अधिसूचना का प्रथम प्रकाशन उ०प्र० गजट में दिनांक 07 अगस्त, 2004 को भाग-8, पृष्ठ संख्या-243 पर हुआ था। योजना के लिये उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-2104/आठ-2-2006-4 एच०बी०/05 दिनांक 29 सितम्बर, 2006 द्वारा 1524.33 एकड़ भूमि पर परिषद को योजना चलाने हेतु अधिनियम की धारा-31 (2) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई। परिषद के अधिनियम की धारा-32 (1) के अन्तर्गत योजना का राजकीय गजट प्रकाशन दिनांक 07 अक्टूबर, 2006 को कराया गया।



योजना में समाविष्ट खसरा सं0-1666 ग्राम बरौली खलीलाबाद की कुल भूमि नमूना फार्म-3 में 19-4-0 बीघा अंकित है। किन्तु खसरे के सभी सह खातेदारों की खतौनियों के अनुसार कुल रकबा 4.920 हे0 है एवं उद्धरण खसरे की बावत सन् 1416 फसली में कुल 4.857 हे0 भूमि दर्ज है। खसरा सं0 1666 ग्राम बरौली खलीलाबाद की 0-19-4 बीघा (0.243 हे0) भूमि योजना की धारा-28 में सम्मिलित है। योजना की धारा-31 की सूची में खसरे की 0.243 हे0 भूमि वन विभाग अंकित करते हुए अर्जन से पृथक किया गया है। तत्क्रम में योजना की धारा-32 एवं परिग्रह पत्र में खसरे की भूमि शून्य है। नियोजन समिति की सर्वे रिपोर्ट में खसरा संख्या 1666 में कुल 06 निर्माण भी अंकित है, जिनका विवरण निम्नवत हैं—

### अनुसूची

क्रमांक	आपत्ति सं0	निर्माण सं0	निर्माणकर्ता का नाम	खसरा सं0	निर्माण का क्षेत्रफल	विवरण धारा-28 का
1	2	3	4	5	6	7
			(सर्वश्री)—		वर्गमीटर—	
7	17,57	884	जगत सिंह	1666	135.20	मकान बना है।
8	20	885	मोहन सिंह	1666	149.76	“
41	49	—	मोहन सिंह रावत	1666	253.00	“
43	51	—	रमेश सिंह	1666	253.00	“
68	—	—	हरी सिंह	1666	126.50	“
69	—	—	हरी सिंह	1666	253.00	“
योग .					1170.46	

खसरा सं0 1666 ग्राम बरौली खलीलाबाद की वर्तमान उद्धरण खतौनियों के अनुसार खसरे की कुल भूमि 4.920 हे0 अंकित है। उक्त भूमि में से वन विभाग कुल भूमि 0.822 हे0 अंकित है, जिससे योजना की धारा-31 में वन विभाग की मात्र 0.243 हे0 भूमि अर्जन से पृथक किया गया है। खसरा सं0 1666 ग्राम बरौली खलीलाबाद की कुल 1.339 हे0 भूमि परिषद द्वारा रजिस्ट्री के माध्यम से क्रय की गयी है।

परिषद की उक्त योजना में समाविष्ट खसरा सं0 1666 ग्राम बरौली खलीलाबाद की कुल 4.920 हे0 भूमि में से वन विभाग की 0.822 हे0 एवं परिषद द्वारा क्रय की गयी 1.339 हे0 तथा नियोजन समिति की परिशिष्ट-12 में चिन्हित निर्माण का क्षेत्रफल 1170.46 वर्ग मीटर अर्थात् 1171.00 वर्ग मीटर (0.1171 हे0) भूमि पृथक करने पर कुल 2.642 हे0 भूमि अवशेष बचती है।

योजना में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा सं0 1666 की अवशेष 2.642 हे0 भूमि के अर्जन हेतु परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में वांछित परिवर्तन के दृष्टिगत मा0 परिषद की 239वी0 बैठक दिनांक 21.10.2016 के मद सं0-239/22 के द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-33 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये ग्राम-बरौली खलीलाबाद, खसरा सं0 1666 की अवशेष 2.642 हे0 भूमि को परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-33 के अर्न्तगत अधिग्रहित करने हेतु प्रेषित प्रस्ताव को शासन के पत्रांक-2100/आठ-2-2024-23 भू0अ0/2018 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30.12.2024 द्वारा शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

**उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-33 (2) में निम्नवत व्यवस्था दी गयी है—**

“33(2) उपधारा (1) के अधीन किसी योजना में किया गया कोई परिवर्तन या निरस्तीकरण गजट में विज्ञापित के दिनांक से इस प्रकार प्रभावी होगा कि किसी परिष्कार का मूल योजना के अन्तर्गत पहले से की किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।”

अतः शासन द्वारा प्रदान की गयी शासकीय स्वीकृति दिनांक 30.12.2024 के क्रम में परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद खसरा संख्या-1666 की अवशेष 2.642 हे० भूमि परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-33 (2) के अन्तर्गत अधिग्रहित की जाती हैं।

डा० बलकार सिंह,  
आवास आयुक्त।

### **Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad**

Under Section-33 & Section-2(3) of Schedule Section-55 read with Section 32(1) of the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad (Act) Adhiniyam, 1965 (Act No.-1 of 1966)

(As amended by Uttar Pradesh Act No.-7 of 2010)

#### **NOTIFICATION**

*June 16, 2025*

**No. 443/L.A.C./H.Q./(File No. 59)**—By the Parishad letter number-1245/L.A.C./H.Q./dated : 17.07.2004, the notification of the scheme was first published in the U.P. Gazette on 07.08.2004 on Part-8, page number-243, by including the remaining land area of 2.642 hectares of Village-Barauli Khalilabad, Khasra number-1666 included in the Parishad Sultanpur Road Land Development and Housing Scheme (Awadh Vihar Scheme), Lucknow. For the scheme, the State Government of Uttar Pradesh by Government Order number-2104/8-2-2006-4 H.B./05 dated 29.09.2006 granted approval to the Parishad under section-31 (2) of the Act to run the scheme on 1524.33 Acres of land. Under Section 32 (1) of the Council Act, the scheme was published in the Official Gazette on 07.10.2006.

The total land of Khasra No. 1666 Village-Barauli Khalilabad included in the scheme is mentioned as 19-4-0 Bigha in Sample Form-3. But according to the Khatauni of all the Co-shared owners of the Khasra, the Total area is 4.920 hectares and in the year 1416-Fasli, a Total of 4.857 hectares of land is recorded in the extracted Khasra 0-19-4 bigha (0.243 hectares) land of Khasra No. 1666 Village-Barauli Khalilabad is included in Section-28 of the scheme. In the list of Section-31 of the scheme, 0.243 hectares of Khasra land has been separated from acquisition by marking it as Forest Department. Accordingly, in Section-32 of the scheme and the acquisition letter, the land of Khasra is zero. In the survey report of the planning committee, a total of 06 constructions are mentioned in Khasra No. 1666, the details of which are as follows:

**SCHEDULE**

No.	Objection no.	Construction no.	Manufacturer's Name	Khasra No.	Area of construction	Description of Section 28
1	2	3	4	5	6	7
			(Mr./Sri)-		In Sq.Mtr.	
7	17, 57	884	Jagat Singh	1666	135.20	The house is built.
8	20	885	Mohan Singh	1666	149.76	"
41	49	--	Mohan Singh Rawat	1666	253.00	"
43	51	--	Ramesh Singh	1666	253.00	"
68	--	--	Hari Singh	1666	126.50	"
69	--	--	Hari Singh	1666	253.00	"
<b>Total .</b>					<b>1170.46</b>	

According to the current extract of Khasra no. 1666 Village-Barauli Khalilabad, the total land of the Khasra is 4.920 hectares. Out of the said land, the total land of the forest department is 0.822 hectares, from which only 0.243 hectares of forest department land has been excluded from acquisition under section 31 of the scheme. A total of 1.339 hectares of land of Khasra no. 1666 Village-Barauli Khalilabad has been purchased by the Parishad through registry.

Out of the total 4.920 hectare land of Khasra No. 1666, Village-Barauli Khalilabad, included in the aforesaid plan of the Parishad, 0.822 hectare belonging to the Forest Department, 1.339 hectare purchased by the Parishad, and the area of construction marked in Appendix-12 of the Planning Committee, measuring 1170.46 square metres, *i.e.* 1171.00 square metres (0.1171 hectare) of land are separated, a total of 2.642 hectare land remains.

In view of the desired changes in the Parishad's Sultanpur Road Land Development and Housing Location Scheme (Awadh Vihar Scheme). Lucknow for the acquisition of the remaining 2.642 hectare land of Khasra No. 1666 of Village-Barauli Khalilabad included in the scheme, by item no. 239/22 of the 239th meeting of the Hon'ble Council dated 21.10.2016, using the power conferred under section-33 of the U.P. Housing and Development Parishad Act, 1965, the proposal sent for acquisition of the remaining 2.642 hectare land of Khasra No. 1666 of Village-Barauli Khalilabad under section 33 of the Parishad Act, 1965 has been given official approval by the Government's letter no. 2100/8-2-2024-23 Bhu.Aa./2018 Housing and Urban Planning Section-2 Lucknow dated 30.12.2024.

**The following provision has been given in Section-33 (2) of the Uttar Pradesh Housing and Development Council Act, 1965 :-**

"33(2) Any modification or repeal made in a scheme under sub-section (1) shall take effect from the date of its advertisement in the Gazette, so that any modification shall not affect the validity of anything previously done under the original scheme."

Therefore, in accordance with the official approval dated 30.12.2024 given by the Government, the remaining 2.642 hectares of land of Village-Barauli Khalilabad, Khasra No.-1666 included in the Council's Sultanpur Road Land Development and Housing Scheme (Avadh Vihar Scheme), Lucknow is acquired under Section-33(2) of the Council Act, 1965.

Dr. Balkar Singh,  
Housing Commissioner.

### कार्यालय, नगर पंचायत किशनपुर, फतेहपुर

17 फरवरी, 2025 ई0

सं0 309/न0पं0 किशनपुर/2024-25—एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा जारी अधिसूचना सं0-912/नौ-9-2024-85ज/05 टी0सी0-01 लखनऊ दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली-2024 को अन्तिम रूप से प्राख्यापित कर दिया गया है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी। उक्त नियमावली के नियम-5 (1) के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत किशनपुर जनपद फतेहपुर की भौगोलिक सीमाओं में स्थित प्रत्येक भवन समूह के लिए फर्शी क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) हेतु न्यूनतम मासिक किराये की दर या प्रत्येक भूमि समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) हेतु न्यूनतम मासिक किराये की दर निर्धारित करती है। नियमावली के नियम-5 (2) के अनुसार अनावासिक भवनों और भूमि के मामले में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर नियमावली के नियम-5 के उपनियम (1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा जैसा कि नियमावली के नियम-5 (2) की अनुसूची की श्रेणी 1, 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित है। नियमावली के नियम-7 के उपनियम (2) के प्राविधानानुसार भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर वार्षिक मूल्य से किसी भी दशा में 10% से कम नहीं होगा। भवनों, भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जलकर 7.5% से कम नहीं होगा और जल निकास कर वार्षिक मूल्य से 2.5% से कम न होगा। नियमावली के नियम-7 (1) के प्राविधानानुसार कर का निर्धारण वार्षिक मूल्य की गणना के अनुसार किया जायेगा। प्रस्तावित न्यूनतम मासिक किराया दर जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं वार्डवार आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु दिनांक 21 जनवरी, 2025 को समाचार-पत्र दैनिक लोक भारती व विश्ववार्ता में प्रकाशित किया गया था। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने उपरान्त उक्त नियमावली के नियम-6(1) के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत किशनपुर जनपद फतेहपुर की भौगोलिक सीमाओं में स्थित प्रत्येक भवन समूह के लिए फर्शी क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) हेतु निर्धारित न्यूनतम मासिक किराये की दर या प्रत्येक भूमि समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) हेतु निर्धारित न्यूनतम मासिक किराये की दर (प्रति वर्ग फुट में) की अंतिम (फाइनल) सूची निम्नवत् है:— यह उपविधि गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

## वर्गवार/श्रेणीवार न्यूनतम मासिक किराये की दर प्रति वर्ग फुट

## समस्त वार्ड पर लागू

09 मी० तक के चौड़ाई वाले मार्ग			09 मी० से अधिक और 12 मी० तक चौड़ाई वाले मार्ग			12 मी० से अधिक और 24 मी० तक चौड़ाई वाले मार्ग			24 मी० से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग			भूमि के सम्बन्ध में			
पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	09 मी० तक अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि	09 मी० से अधिक और 12 मी० तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि	12 मी० से अधिक और 24 मी० तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि	24 मी० से अधिक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि
आर० सी०	आर० सी०	आर० सी०	आर० सी०	आर० सी०	आर० सी०	आर० सी०	आर० सी०	आर० सी०	आर० सी०	आर० सी०	आर० सी०	13	14	15	16
छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	रु०	रु०	रु०	रु०
या	या	या	या	या	या	या	या	या	या	या	या	रु०	रु०	रु०	रु०
आर० बी०	आर० बी०	आर० बी०	आर० बी०	आर० बी०	आर० बी०	आर० बी०	आर० बी०	आर० बी०	आर० बी०	आर० बी०	आर० बी०	रु०	रु०	रु०	रु०
छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	छत	रु०	रु०	रु०	रु०
सहित	सहित	सहित	सहित	सहित	सहित	सहित	सहित	सहित	सहित	सहित	सहित	रु०	रु०	रु०	रु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
0.50	0.40	0.30	0.60	0.50	0.40	0.80	0.70	0.50	1.00	0.80	0.60	0.20	0.30	0.40	0.50

रविन्द्र कुमार,  
अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत किशनपुर,  
फतेहपुर।

## कार्यालय, नगर पंचायत सैदनगली, जनपद-अमरोहा

दिनांक 11 जून, 2025 ई०

सं० 51/न०प०से०/2025-26-नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा अपनी सीमा में स्थित समस्त आवासीय भवनों/अनावासीय/ भू-खण्डों पर गृहकर एवं मानचित्र (नक्शा) शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (संशोधित)-2011 की धारा-128(1), 140(1), 141क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं नगर निकाय अनुभाग-9 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190 द्वि०रा०वि०आ०/दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगर सीमान्तर्गत भवनों/भूमियों तथा सम्पत्तियों के पंचवर्षीय/आकस्मिक गृह निर्धारण हेतु स्वमूल्यांकन (स्वकर प्रणाली) निर्धारण नियमावली एवं मानचित्र (नक्शा) शुल्क वर्ष 2024 बनायी है, जिसका प्रकाशन हिन्दुस्तान समाचार-पत्र एवं अमृत विचार समाचार-पत्र में दिनांक 15.05.2025 में प्रकाशित कराकर 15 दिवस

के अन्दर लिखित रूप में आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे, निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में बोर्ड की बैठक दिनांक 27.03.2025 को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्नवत उपविधि (गजट) प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

### प्रस्तावित उपविधि

**1—नाम—** यह नियमावली स्वकर उपविधि नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा के नाम से जानी जायेगी।

**2—अर्थ—** स्वकर निर्धारण प्रणाली के तहत भवन स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस उपविधि में उल्लिखित दरों के आधार पर आगणन कर भवन पर कर निर्धारण कर सकेगा।

### 3—परिभाषायें इस उपविधि में—

- (1) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा से है।
- (2) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम, 1916 से है।
- (3) "अधिशाली अधिकारी" से तात्पर्य अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा से है।
- (4) "अध्यक्ष/बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा के अध्यक्ष/बोर्ड से है।
- (5) "सम्पत्ति" से तात्पर्य नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा की सीमा में स्थित भूमि/भवन या दोनों से है।
- (6) "स्व-कर निर्धारण" का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस उपविधि से संलग्न प्रपत्र "क" में दाखिल किया जाने वाले स्वतः निर्धारण विवरण से है।
- (7) "आवासीय भवन" से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन में हो और आवासीय उपयोग का प्राविधान हो। किन्तु उसमें व्यवसायिक उद्देश्य से उपयोग के लिये होटल, लाज या किसी अन्य प्रकार के भवन सम्मिलित न होंगे।
- (8) "अनावासीय भवन" से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसका प्रयोग व्यवसायिक/गैर आवासीय गतिविधियों के रूप में हो रहा है।
- (9) "मिश्रित भवन" से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसमें आवासीय के साथ-साथ व्यवसायिक/गैर आवासीय गतिविधियां संचालित हो रही हैं।
- (10) "पक्का भवन" से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसकी दीवार, ईंट/पत्थर या ऐसे ही किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो तथा जिसकी छत आर0सी0सी0 या आर0बी0सी0 पद्धति से निर्मित हो।
- (11) "अन्य पक्का भवन" से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी छत कड़ी, पटियों एवं गार्डरों से निर्मित हो।
- (12) "कच्चा भवन" से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी छत अस्थायी साधनों यथा छप्पर, लोहा/सीमेन्ट की चादर आदि से निर्मित है।
- (13) "मासिक किराया दर" से तात्पर्य नगर पंचायत द्वारा वार्डवार निर्धारित भवनों/भूमि के कारपेट ऐरिया/आच्छादित क्षेत्रफल के लिये निर्धारित प्रति वर्ग फुट मासिक किराये से है।
- (14) "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-140 के अधीन निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है।
- (15) "आच्छादित क्षेत्रफल" से तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है।

- (16) "कारपेट एरिया" से का तात्पर्य अधिनियम की धारा-140 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट कारपेट एरिया से है।
- (17) "मार्ग की चौड़ाई" से तात्पर्य सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर स्थित सरकारी नाली/नाला के बीच की दूरी से है।
- (18) "अधिसूचित बैंक" से तात्पर्य कर की धनराशि को जमा करने के लिए नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंकों से है।

#### 4-कारपेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जायेगी-

- (क) कमरे-आन्तरिक आयाम की पूर्णमाप।
- (ख) आच्छादित बरामदा-आन्तरिक आयाम की पूर्णमाप।
- (ग) बालकनी, कोरीडोर, रसोई व भण्डार गृह-आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।
- (घ) गैराज-आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप।
- (ङ) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको, और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

अथवा

कारपेट एरिया- आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत भाग।

#### 5-वार्षिक मूल्य की गणना निम्नानुसार की जायेगी -

- (1) आवासीय भवनों की वार्षिक मूल्य की गणना -

वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12 ।

या

आच्छादित क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12 × 80 प्रतिशत।

- (2) अनावासीय/गैर आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्य की गणना -

वार्षिक मूल्य = आच्छादित क्षेत्रफल/भूमि का खुला क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 4 (गुणक) × 12 ।

#### 6- स्वतः अध्यासिक आवासीय भवनों के लिये छूट -

- (क) 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (ख) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

#### 7- किराये पर उठे आवासीय भवन -

- (क) (1) 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा।
- (2) 10 वर्ष से 20 तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 12.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा।
- (3) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में आगणित वार्षिक मूल्यांकन के बराबर समझा जायेगा।

(ख) किराये पर उठे अनावासीय/व्यवसायिक भवन का मूल्यांकन अनुबन्ध में उल्लिखित वास्तविक किराये या मासिक किराया दर (प्रतिवर्ग फुट) मूल्यांकन जो अधिक हो, पर किया जायेगा।

**8—रेन्ट कन्ट्रोल के मकान** — रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के आधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होगा। बल्कि इसके किराये का निर्धारण उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 का प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा, ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदारी की होगी।

**9—जिन भवनों में किरायेदार और सर्वे में भवन स्वामी का पता नहीं चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को ही गृहकर का भुगतान करना होगा।**

**10—अनावासीय/गैर आवासीय भवन से तात्पर्य** — सभी प्रकार की फुटकर दुकाने, शोरूम, कृषि उपकरणों का विक्रय केन्द्र, शीतगृह, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, पी0सी0ओ0, पेट्रोल व डीजल फिलींग स्टेशन, गोदाम, बैंक वाणिज्य कार्यालय नार्सिंग होम, अस्पताल, बारात घर, गेस्ट हाउस व अन्य व्यवसायिक भवन/भूमि आदि से है।

**11—अधिनियम की धारा —129क की उपधारा (क) से (छ) को छोड़कर नगर पंचायत सीमा में स्थित समस्त भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का उपग्रहण किया जायेगा।**

**12—वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर आगणित कर से सम्बन्धित आधारभूत तथ्य —**

(क) नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र या उसके भाग में उपविधि में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेंगे। (संशोधित धारा 141)

(ख) उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वयं कर सकता है।

(ग) सर्वेक्षण के दौरान आवासीय और व्यवसायिक भवनों के पृथक-पृथक भवन संख्यायें आवंटित की जायेगी यदि किसी भवन में आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों गतिविधियां पायी जाती है तो दोनों को पृथक पृथक भवन संख्यायें आवंटित की जायेगी।

(घ) अनावासीय/व्यवसायिक भवनों पर कर निर्धारण उपविधि में उल्लिखित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

**13—कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा की सीमा में स्थित भवन/भूमि का स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर का निर्धारण निर्धारित मासिक किरायेदरों (प्रति वर्ग फुट) के आधार पर स्वः मूल्यांकन द्वारा कर लेगे। इसके लिये नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा से एक आवेदन-पत्र (प्रपत्र "क" और प्रपत्र "ख") प्राप्त कर अपने मकान का ब्योरा देकर उपविधि में दी गयी निर्धारित दर के अनुसार स्वयं स्वः कर का निर्धारण करेंगे।**

**14—आवेदन-पत्र (प्रपत्र "क" और प्रपत्र "ख") नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।**

**15—जिन भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी द्वारा स्व-कर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा, तो उनके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा द्वारा की जायेगी।**

**16—भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासियों द्वारा आवेदन-पत्र (प्रपत्र "क" और प्रपत्र "ख") में गलत तथ्य/सूचना देने पर उसको रुपये 1000.00 से अनधिक अर्थदण्ड देय होगा।**

**17—कर निर्धारण दर—गृहकर की देयता वार्षिक होगी जो वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत होगा।**



**18—करों का भुगतान —**

(1) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी बनाये गये नियम अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा में कर का भुगतान किया जायेगा। स्वःकर निर्धारण का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की दशा में उपविधि में दी गयी शास्ति तथा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-173 (क) के भी अनुसार कर की वसूली की जायेगी।

(2) जिन भवनों/भूमि को नगर पंचायत सैदनगली जनपद अमरोहा द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र "क" और प्रपत्र "ख" पर उपरोक्तानुसार भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र "क" के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया कर भी जमा करेंगे।

(3) जब किसी भवन में निर्माण या पुर्ननिर्माण के फलस्वरूप कारपेट एरिया/भूमि के क्षेत्रफल अथवा दोनों में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन किया जाता है तो उसके निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से 03 माह के अन्दर यथास्थिति भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा प्रपत्र "ख" में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित भवन को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में लिया गया हो, तो इसके 03 माह के अन्दर प्रपत्र "ख" में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

**19—करों में छूट —**

(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी, 01 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य कर जमा करने की दशा में चालू मांग में 20 प्रतिशत तथा 01 अगस्त से 31 दिसम्बर के मध्य कर जमा करने की दशा में चालू मांग में 10 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। इसके पश्चात् कर जमा करने पर कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) ऐसे भवन स्वामी/अध्यासी को जिस पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च के पश्चात् बकाया चालू मांग में 05 प्रतिशत अधिक ब्याज देना होगा।

**20—मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी —** कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में अंकित कराना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करने हेतु विचाराधीन है तो उसका उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा अन्यथा उसके बाद कर सूची में आवेदन के अनुसार नाम कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

**21—(क)** नगर पंचायत की ओर से अधिशासी अधिकारी जैसी भी परिस्थिति हो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-158 (1) (2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उसकी सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ख) इस उपविधि के किसी भी प्राविधान, के बारे में बोर्ड यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी भी प्राविधान का दुरुपयोग नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है, अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है, तो उक्त प्राविधान को निरस्त करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

**22—(क)** निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा अपनी सीमान्तर्गत आवसीय भवनों/भूमियों का वार्षिक मूल्यांकन निम्न प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दरों पर निर्धारित किया जायेगा।

क्र० सं०	कक्ष (वार्ड) का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	9 मी० से अधिक पर स्थित भवन			6 मी० से 9 मी० तक चौड़े मार्क पर स्थित भवन			6 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			केवल भूमि/भू-खण्ड के सम्बन्ध में स्थित		
			RCC/ RB छत सहित पक्का भवन पर	अन्य पक्का भवन पर	कच्चा भवन पर	RCC/ RB छत सहित पक्का भवन पर	अन्य पक्का भवन पर	कच्चा भवन पर	RCC/ RB छत सहित पक्का भवन पर	अन्य पक्का भवन पर	कच्चा भवन पर	9 मी० से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भूमि/ भू-खण्ड	6 मी० से 9 मी० तक चौड़े मार्ग पर स्थित भूमि/ भू-खण्ड	6 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूमि/ भू-खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-	1-मेहन्दीपुर ग्राम	आवासीय	0.25	0.15	0.10	0.15	0.10	0.05	0.10	0.05	0.05	0.25	0.15	0.10
2-	1-मेहन्दीपुर पाकबड़ा रोड	आवासीय / अनावासीय	0.80	0.50	0.25	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.80	0.50	0.25
3-	2-सब्दलपुर शर्की	आवासीय	0.25	0.15	0.10	0.15	0.10	0.05	0.10	0.05	0.05	0.25	0.15	0.10
4-	3-अम्बेडकर नगर	आवासीय	0.80	0.50	0.25	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.80	0.50	0.25
5-	4-बगीची	आवासीय	0.80	0.50	0.25	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.80	0.50	0.25
6-	5-चौपपुर सब्दलपुर सब्दलपुर की मढैया	आवासीय	0.25	0.15	0.10	0.15	0.10	0.05	0.10	0.05	0.05	0.25	0.15	0.10
7-	6-शानिदेव मन्दिर	आवासीय	0.80	0.50	0.25	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.80	0.50	0.25
8-	7-इकोंदा पूर्वी, दक्षिणी	आवासीय	0.25	0.15	0.10	0.15	0.10	0.05	0.10	0.05	0.05	0.25	0.15	0.10
9-	8-इकोदा पश्चिमी	आवासीय	0.25	0.15	0.10	0.15	0.10	0.05	0.10	0.05	0.05	0.25	0.15	0.10
10-	9-धर्मशाला ककरूआ	आवासीय	0.25	0.15	0.10	0.15	0.10	0.05	0.10	0.05	0.05	0.25	0.15	0.10
11-	9-धर्मशाला	आवासीय / अनावासीय	0.80	0.50	0.25	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.80	0.50	0.25
12-	10-सादात	आवासीय	0.80	0.50	0.25	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.80	0.50	0.25
13-	11-मनिहारान	आवासीय / अनावासीय	0.80	0.50	0.25	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.80	0.50	0.25
14-	12-रहमत नगर	आवासीय	0.80	0.50	0.25	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.80	0.50	0.25
15-	13-कुरैशियान	आवासीय / अनावासीय	0.80	0.50	0.25	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.80	0.50	0.25
16-	14-अंसारियान	आवासीय / अनावासीय	0.80	0.50	0.25	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.80	0.50	0.25

**22—(ख)** उपविधि के प्रस्तर 10 के अन्तर्गत अनावासीय/गैर आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्य का तात्पर्य उपविधि के प्रस्तर 5 (2) के अनुसार निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल आवासीय मासिक किराया दरों के आधार पर आंगणित वार्षिक मूल्य के 4 गुना मूल्य से है।

**मानचित्र (नक्शा) शुल्क उपविधि :—**

1. आवासीय भवनों/भूखण्डों पर 10 रुपये वर्ग मीटर देना होगा।
2. अनावासीय भवनों/भूखण्डों पर 100 रुपये वर्ग मीटर देना होगा।
3. आवासीय एवं अनावासीय भवनों/भूखण्डों के ओपन ऐरिया पर 05 रुपये वर्ग मीटर देना होगा।

### शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सैदनगली जनपद-अमरोहा यह निर्देश देती है कि—

(1) जो व्यक्ति इस उपविधि के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करेगा, उसे रू0 1,000.00 (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है और जब ऐसा उल्लंघन निरन्तर किये जाने की स्थिति में प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध होगा, रू0 25.00 (पच्चीस रुपये) तक हो सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी इस उपविधि के आधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, अपराध के लिए नियत अर्थदण्ड की अन्यून एक तिहाई धनराशि और अनाधिक आधी धनराशि की वसूली पर अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

सलिल भारद्वाज,  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, सैदनगली,  
जनपद—अमरोहा।

### कार्यालय नगर पंचायत मटौंध, बाँदा

13 जनवरी, 2025 ई0

### अधिसूचना

सं0 819/न0पं0मटौंध/2024-25 नगर पंचायत मटौंध, बाँदा की मा0 सदन की बैठक (बोर्ड बैठक) दिनांक 10 जनवरी, 2025 में पारित संकल्प संख्या—02 द्वारा नगर पंचायत मटौंध, बाँदा द्वारा प्रस्तुत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिए राज्य मॉडल उपविधि को सर्वसम्मति से पास किये जाने के अनुपालन में नगर पंचायत मटौंध के अन्तर्गत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा एवं उसके सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों के आलोक में ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/किट/सोखता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधियों की अधिसूचना के सम्बन्ध में नगर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों/सामाजिक संस्थानों से आपत्ति/सुझाव 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक सामाचार—पत्र आज एवं एक संदेश में दिनांक 18 जनवरी, 2025 को कराया गया था। निर्धारित अवधि 15 दिवस

व्यतीत हो जाने के उपरान्त कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः निम्नलिखित “नगर पंचायत मटौंध, बाँदा फीकल स्लज सेप्टेज प्रबन्धन FSSM उपविधि 2024” की अधिसूचना गजट प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

### क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पंचायत मटौंध बाँदा की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पंचायत मटौंध बाँदा भवनों पर लागू होगा।

**प्राधिकार :** ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है :

- (क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019
- (ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017
- (ग) सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013
- (घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि
- (ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एण्ड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट-2013
- (च) आईएस कोड 2470 भाग-। और भाग-।। 1985 (1996 रीअफर्म्ड)-सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिये कार्य व्यवहार संहिता
- (छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- (झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता सम्बन्धी, जैसे कि यू0पी0 जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

### अध्याय-I

#### प्रारम्भिक-

#### 1-लघु-शीर्षक और प्रारम्भ-

(i) इन उपविधि को 'मटौंध, बाँदा फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन (एफ0एस0एस0 डब्ल्यू0एम0) उपविधि, 2024 कहा जायेगा।

(ii) ये उपविधि, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से नगर पंचायत मटौंध बाँदा की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

#### 2-परिभाषाएँ-

(i) एक्सेस कवर से तात्पर्य है-निरीक्षण, सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यों के लिये ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (ओ0एस0एस0) तक पहुंच के लिये प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपर्युक्त ढक्कन।

(ii) नगर पंचायत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से तात्पर्य है-राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिये विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर जिसका नगर पंचायत मटौंध बाँदा द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफ0एस0एस0) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिये निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

(iii) विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0) एक ऐसी एग्रीगेट है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-अलग पड़े सामुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सज्जन स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल है। डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 से अपशिष्ट जल के तरल-ठोस, दोनों भागों को उपचार किया जाता है।

(iv) निर्दिष्ट अधिकारी से तात्पर्य, स्वयं अधिशाषी अधिकारी अथवा नगर पंचायत का ऐसा अधिकारी, खाद्य एवं सफाई निरीक्षक, कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक आदि, जिसे अधिशाषी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिये अधिकृत किया गया है।

(v) डी-स्लजिंग से लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर अथवा नगर पंचायत मटौध बाँदा के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा ओ0एस0एस0 से एफ0एन0एस0 को खाली करने का काम अभिप्रेत है।

(vi) निपटान से एफ0एस0एस0 का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रभावित करना/ले जाने का कार्य अभिप्रेत है।

(vii) उत्प्रवाही किसी ओ0एस0एस0 से श्रावित द्रव्य है। सैपटेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है।

(viii) फीकल स्लज से ओ0एस0एस0 की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर शहर और शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएँ भण्डारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, ओ0एस0एस0 में भूजल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है।

(ix) "फीकल स्लज व सैपटेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एफएसएसटीपी)" सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिये ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिये एक स्वतंत्र एफएसएस ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एसटीपी) भी अभिप्रेत किया जा सकता है, अगर वहाँ फीकल स्लज/सैपटेज को सीवेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

(x) "लाइसेंस से तात्पर्य है-किसी व्यक्ति को दी गयी लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सैपटेज प्रबंधन (एफएसएसएम) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें नगर पंचायत मटौध बाँदा निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो।

(xi) "लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर" से तात्पर्य है-डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफएसएस के परिवहन के लिये लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति।

(xii) "अधिसूचित स्थान" से तात्पर्य है एफएसएस पहुंचने और निपटान का स्थान जिसे नगर पंचायत मटौध बाँदा द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है।

(xiii) "ऑनलाइन स्वच्छता व्यवस्था (ओएसएम)" ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्था जिसमें मल-मूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है जहाँ उत्पन्न होता है।

(xiv) "प्रचालक" से तात्पर्य है-एफएसएस के डी-स्लजिंग, परिवहन या ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

(xv) "व्यक्ति" प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कम्पनी, व्यक्तियों का एक संगठन या व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है चाहे वह निगमित हो या न हो।

(xvi) "शेडयूल्ड डी स्लजिंग" सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन (सीपीएचईओ) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

(xvii) सैप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है।

(xviii) "सीवेज" अपशिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है।

(xix) "सीवर" से तात्पर्य है—समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करायी गयी भूमिगत पाईपलाइन।

(xx) "सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट" से तात्पर्य है—वह स्थान जहां सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है।

(xxi) "कार्यबल" से तात्पर्य है—शहर में अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत मटौंध, बाँदा की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल। समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों, शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है।

(xxii) "नगर पंचायत के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी" से तात्पर्य है—नगर पंचायत मटौंध, बाँदा के स्वामित्व वाले वैक्यूम टैंकर का उपयोग कर एफएसएस क डी-स्लजिंग और परिवहन के उद्देश्य के लिये नगर पंचायत सेवारत/अनुबंधित कर्मचारी।

(xxiii) "परिवहन" से तात्पर्य है—नगर पंचायत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफएसएस को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना।

(xxiv) "ट्रीटमेंट" से तात्पर्य है—प्रदूषण को कम करने या उसकी रोक थाम के लिये एफएसएस/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने लिये बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया।

(xxv) "वैक्यूम टैंकर" एक ऐसा वाहन है जिसमें एफएसएस को ओएसएस से वायु द्वारा खोंचने के लिये बनाया गया पंप व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लज किये गये एफएसएस के परिवहन के लिये भी किया जाता है।

(xxvi) "अपशिष्ट जल" से तात्पर्य है—घरेलू/व्यावासायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट, जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल है किन्तु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं है। आमतौर पर, यह मलजल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिये बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है।

इन उपविधिया में प्रयुक्त और इन उपविधियाँ में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किन्तु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों में क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर, उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

## अध्याय—II

### अपशिष्ट जल प्रबंधन—

3—परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान—प्रत्येक संपत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किन्तु इन्ही तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्:

(i) यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथा: अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सैप्टिक टैंक से जोड़े।

(ii) अपशिष्ट जल को नगर पंचायत मटौंध, बाँदा द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेन्ट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

(iii) जिस संपत्ति से प्रति दिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डीडब्ल्यूडब्ल्यू टी संस्थापित करेगा ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेन्ट किया जा सके। संपत्ति मालिक (मालकिन), ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/पलशिंग के लिये पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

(iv) परिसर का अपशिष्ट जल ओएसएस में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउटलेट ना हो।

### अध्याय—III

#### ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्थाएं—

#### 4—ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव—

(i) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय—समय पर यथा आशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सीपीएचईईओ के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

(ii) ओएसएस से जुड़ी संपत्ति मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफएसएस की देख-रेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिये उत्तरदायी होगा।

(iii) परिसर का मालिक/धारक नगर पंचायत द्वारा यथा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग अनिवार्य रूप से करायेगा, अन्यथा स्थिति में रु0 5,000/- आर्थिक दण्ड आरोपित किया जायेगा।

(iv) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओएसएस में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफएसएस के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

(v) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुये ओएसएस को यांत्रित रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिये कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

(vi) नगर पंचायत या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिये परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पंचायत मटौंध के मालिक/धारक को एक समय-सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (एफएसएसडब्ल्यू) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग/ गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिये नोटिस जारी कर सकती है।

(vii) नगर पंचायत अपने विवेक से, संपत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिये प्रोत्साहन दे सकती है।

### अध्याय—IV

#### एफएसएस के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग—

#### 5—नगर पंचायत द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना—

(i) नगर पंचायत निजी ऑपरेटरों द्वारा स्वामित्व अथवा किराये पर लिए वैक्यूम टैंकरो का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में मटौंध नगर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ii) नगर पंचायत अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिये इन्फार्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन (आईसीसी) गतिविधियां करेगी, जहां उन्हें एफएसएस को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिये संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 1 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iii) एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन उपविधिया के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुये इसके लिये आवेदन करेगा (करेगी)। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 2 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iv) नगर पंचायत मटौंध, बाँदा एफ0एस0एस0 को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिये ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

(v) लाइसेंस इन उपविधिया के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान आधार पर होगा।

(vi) नगर पंचायत मटौंध, बाँदा आवेदक के स्वामित्व या किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगी। नगर पंचायत अपनी संतुष्टि के लिये वाहन का निरीक्षण करेगी। नगर पंचायत उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय में नगर पंचायत मानते हैं कि इन विनियमों के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा है।

#### 6-लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड-

(i) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2 (xv) में परिभाषित "व्यक्ति" है।

(ii) आवेदक के पास उचित वैक्यूम/संक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराये पर होना/होने चाहिए।

(iii) मटौंध, बाँदा में परिचालन किये जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

(iv) आवेदक नगर पंचायत मटौंध, बाँदा के साथ अपने अपने वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

(v) आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराये पर लिए गए वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते हैं।

(vi) आवेदक नगर पंचायत मटौंध, बाँदा अथवा नगर पंचायत मटौंध, बाँदा द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिये श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

(vii) आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफएसएस के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पीपीई इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

#### 7-लाइसेंस के लिए आवेदन-

एफएसएस के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन उपविधिया के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और नगर पंचायत के निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।



**8—लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिये आवेदकों को आमंत्रण**

नगर पंचायत अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर, संभावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिये आमंत्रित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।

**9—लाइसेंस के लिये आवेदन शुल्क—**

नगर पंचायत लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क 5000.00 प्रभावित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा नगर पंचायत के पक्ष में डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

**10—परफॉरमेंस गारंटी—**

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस (कार्य-प्रदर्शन) गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे उपविधिया के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जाएगा।

**11—लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार—**

नगर पंचायत समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

**12—जागरूकता अभियान—**

नगर पंचायत इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलायेगी, साथ ही साथ एफएसएस को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

**अध्याय—V****एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं परिवहन—****13—संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा—**

(i) एफएसएस की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए नगर पंचायत के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पंचायत के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना संपत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

(ii) मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा (करेगी) कि डी-स्लजों को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन उपविधिया के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफएसएस की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान के रिकॉर्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा (करेगी)।

**14—एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क—**

(i) एफएसएस की डी-स्लज करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को नगर पंचायत के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) नगर पंचायत शहर में शेडयूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को सैनिटेशन चार्ज, द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अथवा इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, संपत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि वसूल नहीं करेगा (करेगी)।

(iv) एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनायेगा और इन उपविधिया के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

#### 15-एफएसएस के परिवहन के लिए वाहन-

(i) एफएसएस को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पंचायत के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा ही डी-स्लज एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जाएगा।

(ii) वैक्यूम टैंकरों को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हो। ऐसे मामलों में, संबंधित ऑपरेटर को इस निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

(iii) एफएसएस के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय-समय पर नगर पंचायत द्वारा चिह्नित किया जाएगा) पर ही चलना होगा।

(iv) एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर नगर पंचायत द्वारा जारी किये गये ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति (कापी) प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

(v) वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जाएगा तथा लाल रंग में "सेप्टिक टैंक वेस्ट" (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व "मलकुंड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिह्नित किया जाएगा।

(vi) एफएसएस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और नगर पंचायत मटौंध, बाँदा द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिए जायेंगे।

#### 16-परिवहन के दौरान सावधानियाँ-

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा (करेगी) कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफएसएस का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

#### 17-दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्मक उपाय-

एफएसएस को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

#### 18-दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता-

किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन सम्पत्ति या पर्यावरण को हुए किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा (होगी), और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया जाता है।

#### 19-तैनात कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय-

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चलित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क, और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन उपविधिया के साथ-साथ "हाथ

से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013'' में तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

## 20—एफएसएस का निपटान—

(i) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय समय पर नगर पंचायत मटौंध, बाँदा द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफएसएस का निपटान करेगा (करेगी)

(ii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफएसएस की डी—स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान का रिकार्ड फार्म नगर पंचायत मटौंध, बाँदा के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगा (करेगी)।

## 21—कर्मियों का प्रशिक्षण—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफएसएस के डी—स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा (होगी)।

## 22—कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा (होगी) कि प्रत्येक कर्मी की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख नगर पंचायत मटौंध, बाँदा को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी), जैसा कि समय—समय पर अधिसूचित किया जाता हो।

## 23—बीमा—

एफएसएस को डी—स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मियों को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013" और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जाएगा।

## 24—लाइसेंस रद्द करना—

इन उपविधिया सहित "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013" के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी), जैसा कि समय—समय पर अधिसूचना किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार परफार्मेंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

## अध्याय—VI

### एफएसएसडब्ल्यू के उपचार एवं पुनः उपयोग/निपटान—

#### 25—उपचार/निपटान स्थान(लों) की पहचान—

नगर पंचायत मटौंध, बाँदा ऐसे स्थानों की पहचान करेगा और अधिसूचित करेगा, जहां एफएसएसडब्ल्यू की लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पंचायत मटौंध, बाँदा के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जाएगा।

#### 26—एफएसएसडब्ल्यू की प्राप्ति हेतु अशोसरचना का सृजन—

नगर पंचायत मटौंध, बाँदा आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगा और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए एफएसएसडब्ल्यू के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

**27—एफएसएस प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती—**

प्रत्येक अधिसूचित स्थानों पर एफएसएस प्राप्त करने और इसे सम्बन्धित उपचार सुविधा में स्थानान्तरित करने हेतु नगर पंचायत मटौंध, बाँदा पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगा।

**28—एफएसएस प्राप्ति का समय—**

नगर पंचायत मटौंध, बाँदा द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घण्टे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थानों पर नगर पंचायत मटौंध, बाँदा के तैनात कर्मियों द्वारा एफएसएस प्राप्त किया जाएगा।

**29—औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए—**

औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफएसएस को अधिसूचित स्थानों पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

**30—एफएसएसएम में प्रशिक्षण—**

नगर पंचायत मटौंध, बाँदा द्वारा अधिसूचित स्थानों पर तैनात कर्मियों को एफएसएस प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

**31—उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का पुनः उपयोग—**

(i) नगर पंचायत मटौंध, बाँदा किसानों को अनुपचारित एफएसएसडब्ल्यू के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी, और एफएसएसटीपी से उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ii) नगर पंचायत मटौंध, बाँदा शहर में डीडब्ल्यूटी से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

(iii) किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्ताव परियोजना के आस-पास के क्षेत्र (1 किमी के दायरों) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिए करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट-जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए नगर पंचायत मटौंध, बाँदा से परामर्श करेगा।

**अध्याय—VII****प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—****32—प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—**

(i) इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार अधिशाषी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित है। जिन्हें विधिवत तौर पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ii) डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत मटौंध, बाँदा समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

**33— निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार—**

इन उपविधिया के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से नगर पंचायत मटौंध, बाँदा के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफएसएसडब्ल्यू उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

**34—उल्लंघन और दंड—**

(i) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा (होगी), यदि ऐसा व्यक्ति (क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है। (ख) इन उपविधियों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गए अधिकार के तहत कार्य करने वाले नगर पंचायत मटौंध, बाँदा के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर को डी-स्लज करने के लिए हाथ से किए जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

(iii) इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और सम्बन्धित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दण्डित किया जाएगा, और साथ ही एफएसएस परिवहन वाहन, एफएसएसडब्ल्यू उपचार सुविधा या सम्पत्ति को जब्त किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(iv) जहां कहीं ऐसे किसी भी मामले में जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाए गए व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपये (रु0 5,000/-) के जुर्माने के साथ दंडित किया जायेगा और इसके बाद निरंतर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपये (रु0 1,000/-) प्रतिदिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जायेगा।

(v) संदेह के समाधान के लिए एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य सम्बन्धित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दण्डित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

### 35-अपील-

कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत नगर पंचायत मटौंध, बाँदा के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो अधिशाषी अधिकारी को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता (सकती) है (इन उपविधियों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर मण्डलायुक्त को प्रस्तुत की जायेगी, जिसके विरुद्ध अपील की गयी थी।

### 36-विवाद समाधान उपलब्ध-

कोई भी विवाद जो इन उपविधियों के संचालन के सम्बन्ध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल झाँसी शहर होगा।

### 37-संदर्भ दस्तावेज-

नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिए, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किए जाएंगे।

### 38-राज्य सरकार के निर्देश इन उपविधियों के पूरक होंगे-

राज्य सरकार इन नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए एफ0एस0एस0 डब्ल्यू0एम0 के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकता है।

**परिशिष्ट-1**

(खण्ड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

**सेप्टिक टैंक का डिजाइन**

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 (भाग 1) 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयू के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

**सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन**

- (1) आयताकार: लंबाई और चौड़ाई का अनुपात: 2 से 4
- (2) गहराई: 1.0 से 2.5 मी. के बीच
- (3) दो कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3
- (4) तीन कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा
- (5) मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- (6) निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

**सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार**

उपयोगकर्ता की संख्या	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी.)
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1: सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2: फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत: सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल — भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

## परिशिष्ट-2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पंचायत मटौध, बाँदा में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की दुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूज़र फीस) की सूची (अनुमानित)

क्र०सं०	श्रेणी	रु. में शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3000 लीटर तक)
1.	कच्चाघर/झोंपड़ी	1500
2.	टिन शेड प्रकार का घर	1500
3.	सभी अन्य घर (पक्का घर)	2500
4.	दुकान	2500
5.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	2500
6.	बैंक	2500
7.	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	2500
8.	रेस्टोरेंट	2500
9.	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2500
10.	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2500
11.	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	2500
12.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	2500
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	2500
14.	3-स्टार होटल	3500
15.	5-स्टार होटल	3500
16.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2500
17.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	2500
18.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2500
19.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2500
20.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2500
21.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2500
22.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2500
23.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2500
24.	मल्टीप्लेक्स	2500
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	2500

26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2500
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2500
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	2500
29.	विवाह हॉल / बैंक्वेट हॉल	3500
30.	बार	2500
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	2500
32.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2500
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	2500
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2500
35.	पैथलॉजिकल लैब	2500
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2500
37.	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	2500
38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	2500
39.	राइस मिल/अन्य मिल	3500
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3500
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	3500

नोट: 1 उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है !

### परिशिष्ट-3

**सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरणों की सूची :-**

**कार्यस्थल पर निम्नलिखित सुरक्षात्मक गियर तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जायेंगे :-**

- शारीरिक सुरक्षा परिधान, जो मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो प्रतिबिम्बित होता और रासायनिक स्प्लैश प्रतिरोध प्रदान करते हैं।
- सेफ्टी बॉडी हार्नेस/सेफ्टी बेल्ट
- सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर्स, जो धूल, धूरें, धुंध, माइक्रोअर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- सेफ्टी टार्च।
- भारी रसायन प्रतिरोध हाथ के दस्ताने जो ब्यूटाइल से बने होते हैं और यांत्रिक सुरक्षा और खतरनाक सामग्री के छलकाव से सुरक्षा देने के लिए अतिरिक्त तौर पर फायदेमंद होते हैं।
- सेफ्टी गॉगल्स (सुरक्षात्मक चश्मे) जिनमें रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता के साथ संक्रामक पदार्थों को आखों तक पहुंचने से बचाने की क्षमता होती है।



- (vii) सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जिसमें एक टार्च लगी होती है और जो कम प्रकाशित स्थानों में कार्य करने में सहायक हो।
- (viii) पुनः उपयोग किया जाने वाला इयरप्लग, जो प्रमुख तौर पर एक लचीली पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे जरूरत न होने पर गर्दन पर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन से बने होते हैं और ये वैक्यूम टैंकरों के ऑपरेशन के दौरान सहायक होते हैं, जहां औसत ध्वनि स्तर B5dBa से अधिक होती है।
- (ix) एमर्जेंसी मेडिकल ऑक्सिजन रिससकिटेटर किट
- (x) गैस मॉनिटर
- (xi) हैड लैम्प
- (xii) गाइड पाइप सेट
- (xiii) सुरक्षा ट्राईपॉड सेट।
- (xiv) वेडर बूट्स।
- (xv) एयर कंप्रेसर और ब्लोअर
- (xvi) मॉड्यूलर एयरलाइस आपूर्ति ट्रॉली सिसटम
- (xvii) रेनकोट

#### परिशिष्ट-4

**फार्म-1 नगर पंचायत मटौंध बाँदा में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिये लाइसेंस आवेदन-पत्र**

तिथि.....

समय .....

#### नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जायेगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ \*septic tank waste\* (अंग्रेजी में) और 'मलकुंड अपशिष्ट' (हिंदी में) लिखा होगा।

19. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

10. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

### परिशिष्ट-5

#### (खण्ड 6 (V) और 8 देखें)

लाइसेंस प्रारूप

नगर निगम/नगर पालिका परिषद .....

#### License for Private Desludging Operator

फॉर्म 2 : फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण

हेतु लाइसेंस प्रदान करना

निकाय ( निकाय का नाम ) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है :

1 :- आवेदक का नाम : (श्री/सुश्री) : .....

2 :- पत्राचार का पता : .....

3 :- निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) का नाम में फीकल स्लज/ सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिये लाइसेंस संख्या : .....

4 :- मान्यता ..... से ..... तक

5 :- वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नम्बर : (I) ..... (II) .....

(III) ..... (IV) .....

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गयी शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज  
निकालने वाले  
ऑपरेटर/ठेकेदार का  
निकाय मोहर के साथ  
एक पासपोर्ट साइज  
फोटो चिपकायें

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

**नियम व शर्तें**

- 1 :— फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू0एल0बी0 द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।
- 2 :—निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए शुल्क यू0एल0बी0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
- 3 :—फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू0एल0बी0 द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।
- 4 :—लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
- 5 :—फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
- 6 :—अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
- 7 :—फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।
- 8 :—वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग से सावधानी के साथ “Septic tank Waste” (अंग्रेजी में) और “मलकुंड अपशिष्ट” (हिंदी में) लिखा होगा।
- 9 :—निर्दिष्ट उपचार संयंत्र साप्ताह में XY दिनों पर X:am से Y:pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
- 10 :—प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
- 11 :—उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिये उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

## परिशिष्ट-6

## (खण्ड 13 (ii) और 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्डफॉर्म 3 : फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

(यू0एल0बी0 का नाम) में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए  
दिनांक : ..... समय : .....

## I :- ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

1. नाम : .....

2. पता : .....

(क) वार्ड संख्या : .....

(ख) टेलीफोन नं0 : .....

## II :- रोकथाम

1. निर्माण का वर्ष ..... 2. पिछला कीचड़ निकालना (दिनांक) .....

3. आउटलेट मौजूद (हां/नहीं) : ..... 4. यदि हां, तो किससे जुड़ा है : .....

5. रोकथाम के प्रकार : (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिक टैंक ट्विन		ट्वीन पिट (पंक्तिबद्ध)	
संग्रह टैंक		ट्विन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गढ़दे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6. रोकथाम का आकार और आकार : नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें।

7. संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान : (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे में फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

## III :- कीचड़ साफ करना

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर) ..... 2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समय .....

3. ट्रिप की लंबाई (कि0मी0) ..... 4. आने-जाने का समय .....

## IV :- कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम : .....

ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर : .....

ड्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर

उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

## परिशिष्ट-7

## (खण्ड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

## होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन-प्रारूप

फॉर्म 4: 'होस्ट यूएलबी' पर उपलब्ध 'उपचार संयंत्र' में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाइजेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, 'होस्ट यूएलबी' (होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत 'उपचार संयंत्र' पर, समझौता।

प्रथम पक्ष 'होस्ट यूएलबी' (होस्ट निकाय का नाम)

द्वितीय पक्ष 'एक्सवाइजेड यूएलबी' (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

## उपबन्ध:

1. यह कि 'प्रथम पक्ष' दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) तक 'द्वितीय पक्ष' की प्रशासनिक सीमाओं से उनके 'उपचार संयंत्र' पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। /वर्ष (अंतिम तिथि)

2. 'प्रथम पक्ष' अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने 'उपचार संयंत्र' पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3. यह कि 'द्वितीय पक्ष' समझ के अनुसार 'प्रथम पक्ष' को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु. ••• देने के लिए सहमत है।

4. यह कि 'प्रथम पक्ष' उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझायें।

6. कि 'द्वितीय पक्ष' केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर 'द्वितीय पक्ष' की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

## परिशिष्ट-8

## जुर्माना और फाइन

क्रम संख्या	विवरण	खंड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा (रु0 में)	जुर्माना (रु0 या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16,17	1000	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16,17	1500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16,17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27,28,33	5000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27,28,33	5000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27,28,33	1000	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकायद्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6,7,14,27, 28,29	5000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6,7,14,27,28,29	5000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6,7,14,27,28,29	150 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

सुधीर सिंह,  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत मटौध, बाँदा।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राज कुमारी पत्नी दिगम्बर प्रसाद मिश्र है, जो मेरे पति की सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में, निर्वाचन कार्ड तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार संख्या-3770 9478 9434 में मेरा नाम राम कुमारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राज कुमारी पत्नी दिगम्बर प्रसाद मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राज कुमारी,  
पत्नी स्व० दिगम्बर प्रसाद मिश्र,  
निवासिनी-ग्राम वृसिंहपुर उर्फ रामगढ़,  
पो० न्यायीपुर, तहसील सोरांव,  
जनपद प्रयागराज, उ०प्र०।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम राजेन्द्र प्रसाद बाजपेई, अंग्रेजी में RAJENDRA PRASAD BAJPAI है। जो मेरे पिता के हाई स्कूल अंक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा मेरी इण्टरमीडिएट के अंक प्रमाण-पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण-पत्र (CBSE BOARD) अनुक्रमांक-5153816 सत्र 2019 में पिता का नाम राजेन्द्र प्रसाद बाजपेई, अंग्रेजी में RAJENDRA PRASHAD BAJPAI अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनुष्का बाजपेई,  
पुत्री राजेन्द्र प्रसाद बाजपेई,  
नि०-588/609, बंगला बाजार, लखनऊ।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम रौनक पुत्री राज करन है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं०-5847 8002 3270 में उसका नाम रविता पटेल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम रौनक पुत्री राज करन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राज करन,  
पता- मेदनी सिंह का पुरा,  
धरवारा, करछना प्रयागराज।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वेदविद पाण्डेय (VEDVID PANDEY) पुत्र अतिशय कुमार पाण्डेय (ATISHAY KUMAR PANDEY) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-4363 1983 4455 में उसका नाम आरुष पाण्डेय (ARUSH PANDEY) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वेदविद पाण्डेय (VEDVID PANDEY) पुत्र अतिशय कुमार पाण्डेय (ATISHAY KUMAR PANDEY) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अतिशय कुमार पाण्डेय,  
(ATISHAY KUMAR PANDEY)  
पुत्र आनन्द कुमार,  
पता- ग्राम बीरपुर पो०-दुमदुमा,  
उस्मापुर उपरहार तहसील-हडिंया,  
जिला प्रयागराज, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति गुप्ता पुत्री नवीन कुमार गुप्ता है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या— 5968 8001 3814 में उसका नाम काव्या गुप्ता अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकृति गुप्ता पुत्री नवीन कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नवीन कुमार गुप्ता,  
पुत्र स्व० विजय नारायण गुप्ता,  
निवासी—172/213 बाजार झाऊलाल,  
अमीनाबाद पार्क, लखनऊ, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम तेजस कुमार पुत्र शैलेन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 6146 0480 9613 में उसका नाम सरगम कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम तेजस कुमार पुत्र शैलेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शैलेन्द्र कुमार,  
एल०आई०जी—74, नई कालोनी,  
देवघाट, झलवा, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम एंजेल श्रीवास्तव पुत्री स्व० अनुज कुमार श्रीवास्तव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित

है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या—2777 4309 1526 में उसका नाम अनुष्का श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम एंजेल श्रीवास्तव पुत्री स्व० अनुज कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रश्मी श्रीवास्तव,  
पत्नी स्व० अनुज कुमार श्रीवास्तव,  
पता— बी—102 प्लॉट नम्बर—48,  
विमल नगर, कमता, चिनहट, लखनऊ, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सलोनी कुमारी पुत्री कृष्ण कुमार सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—7656 8765 7892 में उसका नाम छोटू कुमारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सलोनी कुमारी पुत्री कृष्ण कुमार सिंह से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

माधुरी देवी,  
पत्नी कृष्ण कुमार सिंह,  
नि०—वार्ड नं० 2 गोविन्द नगर, कोरांव,  
जनपद प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनुष्का पुत्री उमाकान्त है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 9336 6797 2509 में उसका नाम श्रेया अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनुष्का पुत्री उमाकान्त के नाम से जाना व पहचाना जाय।



एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

उमाकान्त पुत्र छेदीलाल,  
निवासी— ग्राम मटका पो0 सलोन,  
जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति कुमारी पुत्री धर्मेन्द्र कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 4923 1491 7619 में उसका नाम जैनिथ कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकृति कुमारी पुत्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

धर्मेन्द्र कुमार,  
तिगनौता मन्ना का पूरा डाण्डी,  
नैनी, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंशुमान चौबे पुत्र अजीत चौबे है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6483 4048 0841 में उसका नाम अंश चौबे अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंशुमान चौबे पुत्र अजीत चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अजीत चौबे,  
पुत्र पंचम चौबे,  
निवासी—बलीपुर, छाता, बलिया, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सौम्या गुप्ता पुत्री आनन्द अग्रहरी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। भूलवश मेरे आधार कार्ड संख्या— 8415 1580 8741 में मेरा नाम कृति अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सौम्या गुप्ता पुत्री आनन्द अग्रहरी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सौम्या गुप्ता,  
पुत्री आनन्द अग्रहरी,  
पता—वार्ड नं0 12 किदवई नगर सैयदराजा,  
ब्लाक—बरहनी, जनपद—चन्दौली (उ0प्र0)।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रतिमा सिंह पुत्री राम विशाल है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या—6233 5304 3290 में उसका नाम अर्पिता अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम प्रतिमा सिंह पुत्री राम विशाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रामविशाल पुत्र मीतल प्रसाद जी,  
निवासी— चिल्ला शहबाजी, पोस्ट सैयद सरावां,  
जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अमिश यादव पुत्र सत्येन्द्र कुमार यादव है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—9478 8792 5778 में मेरा नाम अमिश सत्येन्द्रकुमार यादव हो गया है जो कि गलत है। मुझे मेरे

सही नाम अमिश यादव पुत्र सत्येन्द्र कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अमिश यादव,  
पुत्र सत्येन्द्र कुमार यादव,  
पता-4/6 टाईप-3 पी0 डब्लू0डी0 कालोनी,  
जेल रोड, लखनऊ।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य यादव पुत्र सत्येन्द्र कुमार यादव है जो कि उनके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7072 5988 9399 में उसका नाम आदित्य सत्येन्द्रकुमार यादव हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का उसके सही नाम आदित्य यादव पुत्र सत्येन्द्र कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सत्येन्द्र कुमार यादव,  
पुत्र आदित्य यादव,  
पता-4/6 टाईप-3 पी0 डब्लू0डी0 कालोनी,  
जेल रोड, लखनऊ।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रान्शी मिश्रा पुत्री नीरज कुमार मिश्रा है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5610 0751 4744 में उसका नाम मीना अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रान्शी मिश्रा पुत्री नीरज कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नीरज कुमार मिश्रा,  
पता-ग्राम अनंतराम पट्टी,  
पो0 हरिहरपुर बेदौली तहसील सदर,  
जिला मीरजापुर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आनवी पुष्पाकर (AANVI PUSHPAKAR) पुत्री दीपक कुमार पुष्पाकर है जो मेरी पुत्री के शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-3603 6020 1279 में मेरी पुत्री का नाम आनवी पुष्पाकर (AARNAVI PUSHPAKAR) हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री का सही नाम आनवी पुष्पाकर (AANVI PUSHPAKAR) पुत्री दीपक कुमार पुष्पाकर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दीपक कुमार पुत्र राम चन्द्र पुष्पाकर,  
निवासी सराय बहेलिया, रामपुर,  
गौरी प्रतापगढ़।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सिद्धिदा सिंघ पुत्री शिव शंकर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8965 3137 5058 में उसका नाम मुक्ता श्री अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सिद्धिदा सिंघ पुत्री शिव शंकर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिव शंकर पुत्र सतई राम,  
निवासी कसौझा उर्फ पूरे मवैया,  
हिन्दवानी, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शाश्वत शुक्ला पुत्र कमलेश शुक्ला है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० -8239 4184 8578 में उसका नाम विशाल शुक्ला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शाश्वत शुक्ला पुत्र कमलेश कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ज्ञान देवी,  
पत्नी स्व० कमलेश कुमार शुक्ला,  
परमानन्दपुर, हण्डिया।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम गौरवी तिवारी पुत्री कामेश्वर तिवारी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-3217 0064 1354 में उसका नाम अक्षिता तिवारी अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम गौरवी तिवारी पुत्री कामेश्वर तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कामेश्वर तिवारी पुत्र श्री ज्ञानेश्वर तिवारी,  
निवासी ग्राम चाका नैनी, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कृतिका राय पुत्री कविंद्र राय है जो कि शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 7062 7364 9395 में उसका नाम कंतिका राय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कृतिका राय पुत्री कविंद्र राय के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कविंद्र राय,  
पता-न्यु सेंट जेंट्स कॉलोनी,  
यमुना लेन, मझौली, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शालिनी भदौरिया पुत्री पंचम सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-6352 8163 4368 में मेरा नाम शालू पुत्री पंचम सिंह हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शालिनी भदौरिया पुत्री पंचम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शालिनी भदौरिया पुत्री श्री पंचम सिंह,  
पता-ग्राम कसौगा पो० गाँती,  
जिला इटावा।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम महिमा भदौरिया पुत्री पंचम सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-4845 0361 3330 में मेरा नाम शलोनी पुत्री पंचम सिंह हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम महिमा भदौरिया पुत्री पंचम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

महिमा भदौरिया पुत्री पंचम सिंह,  
पता-ग्राम कसौगा पो० गाँती,  
जिला इटावा।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अरविन्द यादव पुत्र जानकी यादव है जो मेरे कक्षा-8 के टी0सी0, निर्वाचन कार्ड, खतौनी तथा परिवार रजिस्टर एवं उप जिलाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट में अंकित है। गलती से मेरे आधार कार्ड सं0—9798 2849 5039 में मेरा नाम विजय यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अरविन्द यादव पुत्र जानकी यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरविन्द यादव पुत्र जानकी यादव,  
ग्राम नरसिंह डाड वागर पो0 व थाना मईल,  
तहसील वरहज जिला देवरिया।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिनन्दन कुमार सिंह पुत्र गोविन्द कुमार सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—4074 8905 4965 में उसका नाम वीर प्रताप सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिनन्दन कुमार सिंह पुत्र गोविन्द कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गोविन्द कुमार सिंह,  
पुत्र स्व0 शिव जी सिंह,  
सा0 व पो0 गोन्हिया छपरा,  
तहसील बैरिया जिला बलिया उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रियल मद्धेशिया (PRIYAL MADDHESHIYA) पुत्री अवधेश कुमार गुप्ता है। जो

उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0—6426 4693 0762 में उसका नाम उज्जवला मदेशिया (UJJAWALA MADESHIYA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम प्रियल मद्धेशिया (PRIYAL MADDHESHIYA) पुत्री अवधेश कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अवधेश कुमार गुप्ता,  
पुत्र स्व0 त्रिवेणी प्रसाद,  
ग्राम व पो0—जलालाबाद तहसील जखनियॉ,  
जनपद गाजीपुर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सृजन जायसवाल (SRIJAN JAISWAL) पुत्र सुशील कुमार जायसवाल (SUSHIL KUMAR JAISWAL) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—4462 6790 7823 में उसका नाम राम जायसवाल (RAM JAISWAL) हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सृजन जायसवाल (SRIJAN JAISWAL) पुत्र सुशील कुमार जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुशील कुमार जायसवाल,  
पुत्र शिवा लाल जायसवाल,  
नि0—ग्राम सेमरा कल्बना पो0 धूरपुर जसरा,  
जनपद प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्राची कुशवाहा पुत्री अशोक कुमार है

जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8521 0191 7845 में उसका नाम खुशी कुशवाहा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्राची कुशवाहा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अशोक कुमार,  
ग्राम पेंवर, अभयपुर,  
तहसील करछना, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रिषभ द्विवेदी पुत्र मोहन चन्द द्विवेदी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5683 8910 6898 में उसका नाम अनिकेत द्विवेदी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रिषभ द्विवेदी पुत्र मोहन चन्द द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मोहन चन्द द्विवेदी,  
पुत्र श्री राम कृष्ण द्विवेदी,  
निवासी -ग्राम खोदाईपुर कला, पो0 बबुराकलां,  
थाना हालिया, मिर्जापुर (उ0प्र0)।

### सूचना

मेसर्स दीपचन्द सुन्दर लाल, पता- 98, राइटगंज, गाजियाबाद पंजीकरण संख्या 27105-एम दि० 27 मार्च, 2014 है। फर्म की पार्टनरशिप डीड दि० 26 सितम्बर, 1991 के अनुसार पार्टनर 1- श्री सुन्दर लाल, 2-श्री मुकेश मित्तल, 3- श्री पंकज मित्तल थे। फर्म की Reconstitution Of Partnership Deed (संशोधित डीड) दि० 30 मार्च, 2025 के अनुसार साझीदार श्री सुन्दर

लाल मित्तल सेवानिवृत्त हो गये हैं नवीन साझीदार की हैसियत से श्री अभिषेक मित्तल व श्री शिवांक मित्तल फर्म व्यवसाय में सम्मिलित हुये हैं। फर्म में वर्तमान पार्टनर 1-श्री मुकेश मित्तल, 2- श्री पंकज मित्तल, 3- श्री अभिषेक मित्तल 4- श्री शिवांक मित्तल है। फर्म साझीदार श्री मुकेश मित्तल व श्री पंकज मित्तल का पता- एल-21, नेहरू नगर थर्ड, गाजियाबाद-201001 हो गया है।

मुकेश मित्तल,  
साझीदार

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s S.S. STEELS पता- ई-77, बुलन्दशहर रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद उ०प्र०-201009 पंजीकरण संख्या- GHA/0006908 की पार्टनरशिप डीड दि० 01 अप्रैल, 2023 के अनुसार सभी साझीदारों की आपसी सहमती से फर्म साझीदार श्री दीपक अग्रवाल एवं श्री राजीव अग्रवाल सेवानिवृत्त हुये हैं। श्री सुनील कुमार जैन पुत्र श्री दया चन्द जैन पता- केजे-65, कविनगर, गाजियाबाद नये साझीदार की हैसियत से सम्मिलित हुआ है। फर्म में वर्तमान साझीदार 1- श्री सचिन जैन, 2- श्री सुनील कुमार जैन है। फर्म का वर्तमान पता-प्लॉट न०-28, लोहा मण्डी, जी.टी. रोड, गाजियाबाद हो गया है।

सचिन जैन,  
साझीदार

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आर० एम० इन्टरप्राइजिज पता 03 ब्लॉक सी-1ए सैक्टर-4 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है पार्टनरशिप डीड 20 दिसम्बर, 2010 के अनुसार फर्म में दो पार्टनर थे (1) श्रीमती रिजवाना कुरेशी पत्नी श्री नवाब कुरेशी जी (2) श्रीमती मुर्ति देवी पत्नी श्री विश्वनाथ जी थी। यह कि फर्म कि संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के अनुसार फर्म में दिनांक 15 अप्रैल, 2021 में साझीदार न०- 2 श्रीमती मुर्ति देवी पत्नी श्री विश्वनाथ जी का निधन हो गया है तथा अब इनके स्थान पर दिनांक

16 अप्रैल, 2021 को नये साझेदार श्री देशराज सिंह पुत्र स्व० विश्वनाथ जी स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार आये हैं व साझेदार की आपसी सहमती से फर्म में क्रमशः दो साझेदार हो गये हैं। अब क्रम से 1- श्रीमती रिजवाना कुरेशी पत्नी श्री नवाब कुरेशी जी 2- श्री देशराज सिंह पुत्र स्व० विश्वनाथ जी साझेदार हो गये हैं।

श्रीमती रिजवाना कुरेशी,  
साझेदार

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की फर्म मेसर्स नारायण इण्टरप्राइजेज, मकान नं०-116एम० ग्राम बिन्दलपुर, बांसगांव कालोनी, जनपद-गोरखपुर उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 01 मई, 2024 से श्री राजवंश सिंह व श्री जयनारायण सिंह एवं श्रीमती रीना सिंह जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पत्रावली सं० G-5175 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदार श्री राजवंश सिंह जी का दिनांक 19 फरवरी, 2025 को मृतक हो चुके हैं तथा वर्तमान में साझेदारी डीड दिनांक 21 फरवरी, 2025 के अनुसार जयनारायण सिंह एवं श्रीमती रीना सिंह जी हैं। उक्त फर्म में कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

जयनारायण सिंह,  
साझेदार,  
मेसर्स नारायण इण्टरप्राइजेज,  
मकान नं०-116एम० ग्राम बिन्दलपुर,  
बांसगांव कालोनी, जनपद-गोरखपुर उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अल्ट्राएग्रीटेक बायोऑर्गेनिकस पता 93, सिटी हार्ट कालोनी, स्टेडियम रोड, बरेली उत्तर प्रदेश जिसकी पंजीकरण सं०-BAR/0014211 में दो साझेदार श्री सनी अग्रवाल पुत्र श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल व श्रीमती गरिमा अग्रवाल पत्नी श्री सनी अग्रवाल स्वेच्छा से व अन्य साझेदारों की सहमति से दिनांक 01 मार्च, 2025 को सम्मिलित हो गये हैं। नये साझेदारों के सम्मिलित होने के

पश्चात पूर्व दोनों साझेदार आइटवो विजनिंस एसोसियेटेड प्राइवेट लिमिटेड (वतौर डायरेक्टर गरिमा अग्रवाल) व श्रीमती शैल अग्रवाल पत्नी श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल दिनांक 01 मार्च, 2025 को ही स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात दोनों सेवानिवृत्त साझेदारों का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त दोनों साझेदारों पर कोई शेष वकाया नहीं है। वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल दो साझेदार कमशः 1- सनी अग्रवाल 2- गरिमा अग्रवाल हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारितायें पूर्ण कर ली गयी हैं।

गरिमा अग्रवाल,  
साझेदार,  
मेसर्स अल्ट्राएग्रीटेक बायोऑर्गेनिकस,  
पता 93, सिटी हार्ट कालोनी, स्टेडियम रोड,  
बरेली उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स पारस फ्यूल्स, पता:-डी-418, शास्त्री नगर, अशोक पार्क, मेरठ उ०प्र० की साझेदारी में श्री प्रशांत जैन, श्री बीना जैन एवं सुधा कंसल साझेदार थे तथा संशोधित साझेदारी डीड दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के अनुसार फर्म से श्री बीना जैन एवं श्री सुधा कंसल फर्म से अपना हिसाब किताब ले व देकर अलग हो गये हैं एवं श्री इक्ष्वांकू गोगीया एवं श्री राजीव अग्रवाल फर्म में नये साझेदार आ गये हैं। संशोधित साझेदारी डीड दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के अनुसार फर्म में श्री प्रशांत जैन, इक्ष्वांकू गोगीया एवं श्री राजीव अग्रवाल फर्म तीन पार्टनर वर्तमान में कार्यरत रहेगे। श्री प्रशांत जैन, इक्ष्वांकू गोगीया एवं श्री राजीव अग्रवाल उपरोक्त फर्म में साझेदार हैं।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रशांत जैन,  
साझेदार,  
मेसर्स पारस फ्यूल्स,  
पता:-डी-418, शास्त्री नगर,  
अशोक पार्क, मेरठ उ०प्र०।

**NOTICE**

It is informed to the general public that my correct name is "MEENA JAIN" W/o Late Naresh Chand Jain which is mentioned in my Aadhaar Card, PAN Card and in my pension records., By mistake in Reliance Industries Limited, Folio No. 070777568 and in Jio Financial Services Limited, Folio No. 070777568 my name "MEENA" has been mentioned at JT1 which is wrong. Both the above names are mine. In future I should be known and identified by my correct name "MEENA JAIN" wife of Late Naresh Chand Jain. It is hereby certified that all the legal formalities in relation to the above have been completed by me.

MEENA JAIN,  
Add. B-2, M.I.G. Napier Rd,  
Colony Part-1, Thakurganj,  
Lucknow-226003 (U.P.)

**NOTICE**

THIS is to notify that in my Son's Adhaar No. 623849305792 his name is inadvertantly mentioned as Satvik Singh which is incorrect. His correct name is Shiva Singh which is mentioned in his Birth and other Certificates which should be rectified for future purposes.

Mithilesh Singh,  
S/o Late Vijay Shankar Singh,  
Vill. Post Dhaurahra,  
Distt-Varanasi.

**सूचना**

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० राहुल रोड कैरियर, बी-12 श्रीजी धाम गोवर्धन रोड, मथुरा-281001 के विघटन की सूचना इस प्रकार हैं -

यह है कि उपरोक्त साझेदारी फर्म तीन साझेदारों रघुवीर सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी-89 सैक्टर-4 राधापुरम् एस्टेट गनेसरा, मथुरा प्रथम पक्ष श्री संदीप लाहोटी पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार लाहोटी निवासी-बी-12 श्रीजी धाम, गोवर्धन रोड, मथुरा द्वितीय पक्ष तथा श्री कौशल बमील पुत्र श्री महावीर सिंह, निवासी- ग्राम बलरई बलरई बांगर, मथुरा तृतीय पक्ष के द्वारा संचालित की जा रही थी किन्तु अपरिहार्य कारणवश व्यवसाय के संचालित न होने के कारण दिनांक 23 जून, 2025 को तीनों साझेदारों की आपसी सहमति से साझेदारी फर्म विघटित कर दी गई हैं।

रघुवीर सिंह,  
साझेदार,  
मे० राहुल रोड कैरियर, बी-12,  
श्रीजी धाम गोवर्धन रोड, मथुरा।

**सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० थालीवाला लक्ष्मी नारायण टैम्पल शॉप सीएचएच मथुरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-

दिनांक 15 जून, 2025 को श्री बालकिशन चतुर्वेदी पुत्र श्री कान्तानाथ चतुर्वेदी निवासी- मनोहरपुरा मथुरा एवं श्रीमती प्रीती चतुर्वेदी पत्नी श्री बाल किशन चतुर्वेदी निवासी- मनोहरपुरा मथुरा अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हुये तद्दिनांक को श्री कमलेश चतुर्वेदी पुत्र स्व० प्रेम चतुर्वेदी निवासी-955 नारायण निवास श्याम घाट मथुरा फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुई अब वर्तमान फर्म में भागीदार श्रीमती साधना चतुर्वेदी एवं कमलेश चतुर्वेदी है।

श्रीमती साधना चतुर्वेदी,  
साझेदार  
मे० थालीवाला लक्ष्मी नारायण टैम्पल,  
शॉप सीएचएच मथुरा।

### सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० चाहर ब्रदर्स, ग्राम बाद पोस्ट ककुआ तहसील सदर, आगरा-282009 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं—

यह है कि दिनांक-09 जून, 2025 को फर्म के साझेदार श्री जुगेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी -20 धर्मलोक नगर, महोली रोड, मथुरा तथा श्री बृजवीर सिंह पुत्र स्व० अचल सिंह निवासी-हथकौली, पोस्ट बल्देव, तहसील महावन, मथुरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा उक्त दिनांक-09 जून, 2025 को ही डा० जसवन्त सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह निवासी-51/10/6 ए, 68 वैस्ट अर्जुन

नगर, शाहगंज, आगरा, श्रीमती राखी सिंह पत्नी श्री जसवन्त सिंह निवासी-51/10/6 ए, 68 वैस्ट अर्जुन नगर, शाहगंज, आगरा तथा श्रीमती पूनम सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह निवासी-पोस्ट दौरैठा, वानपुर, नगला हीरामन, आगरा उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गयी है। वर्तमान में श्री मनमोहन सिंह, श्री जुगेन्द्र सिंह चौधरी तथा श्री बृजवीर सिंह जी साझेदार है।

मनमोहन सिंह,  
साझेदार,

मे० चाहर ब्रदर्स, ग्राम बाद पोस्ट ककुआ,  
तहसील सदर, आगरा।